पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW & P M

W ebite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 4 अंक 26 प्रति सोमवार इंदौर, 27 दिसंबर 2010 से 2 जनवरी 2011 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

चीनी प्रधानमंत्री जियो बाओ की भारत यात्रा

चीनी कम-चीटिंग ज्यादा

मीडिया ने सवाल पूछे तो रिश्तों को समाप्त करने की कोशिश कहा

भारत में हाल ही में चीनी प्रधानमंत्री थेन जिया बाबा ओर उनके 200 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने यात्रा की; बेशक तिब्बितयों ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया जिसे भारत शासन का मूलक समर्थन प्राप्त था। उनके प्रदर्शनों में तिब्बत को स्वतंत्र करने और निर्दोष तिब्बितयों की हत्या करने की मांग के लिए प्रदर्शन भी किया था।

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन का यहां भी रुख काफी ढीला रहा। चीन ने सीमा विवाद, ब्रह्म पुत्र का पानी चुराने और उस पर चीन में बांध बनाने, पाकि अधिकृत कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने, तिब्बत से लेकर वर्मा की सीमा तक सैन्य गतिविधियां बढ़ाने, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने, पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध शह देने, सीमा पर विवादों को रोकने, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, 1962 के युद्ध में 1 लाख किमी से ज्यादा जगह हड़पने के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। यह भारतीय हितों के साथ चीटिंग थी।

भारत में बराक ओबामा आया 10 अरब डालर का माल बेच गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति सरकोजी आये, परमाणु संयंत्र बेंच गये, चीनी 160 अरब डालर के व्यापार समझौते कर गये अब रूसी राष्ट्रपति आ रहे हैं, इन्हें भी अपने हथियार, जहाज, पनडुब्बीयां व अन्य सामग्री बेंचना है। 10-20 अरब डालर का ये भी माल बेंच जायेंगे। हमारे यहां आस्ट्रेलियन गोबर भी खरीदा है, कांग्रेस ने और कमीशन के लिए सरकारी पैसे परमाणु धर्मी कचरा भी।

बस पाकिस्तान से जरदारी अपने आईएसआई के 100-200 आतंकवादियों को लाकर यहां से चना और कांग्रेस का कमीशन डकार कर उन्हें खरीदना भर बचा है। इसलिए संकर संतति राहुल हिन्दुओं का आतंकवादी करार देकर मुस्लिम आतंकियों की पैरवी कर उनसे देशी फसल का उपयोग पर निर्भर करते हैं। बदले में आर.एस.एस. के कट्टर हिन्दुओं को आतंकवादी करार देकर उनकी खबरें मीडिया में छपवाकर हिन्दुओं को आतंकित करने का प्रयास करते हैं।

दूसरी ओर घर आये दुश्मन चीनीयों को सरमाथे पर बैठाकर उनसे व्यापार समझौते तो करते हैं परनतु चीनी घुसपैठ, भारतीय सीमाओं पर रेल लाइन, हवाई अड्डे, सैनिक अड्डों के बारे में अपने पूर्वज स्व. मोहनदास करमचंद गांधी के तीन बंदरों की भांति आंख, कान और मुंह पर हाथ रखकर दुश्मनों के सामने नत मस्तक हो उनकी हर छल, कपट और चीटिंग को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।

धन्य है कांग्रेसी गिरोह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जरदारी को भी आमंत्रित कर उनसे भी हजार दो हजार आतंकी खरीद लो उसमें न केवल कमीशन मिलेगा वरन चारों तरफ से अपने भ्रष्टाचार के कुकर्मों में उलझ जाओ तो आतंकवादियों को देश के मंदिरों, पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर या अन्य भीड़ वाले क्षेत्रों में हमले करने के लिए कह देना ताकि मीडिया और जनता व जनप्रतिनिधियों को हल्ला मचाने से रोका जा सके, जैसी कि तुम्हारे गिरोह की परंपरा रही है।

चीन ने 1958-59 में भी पहले चीनी-हिन्दी भाई-भाई कहकर 1 लाख किमी से ज्यादा जमीन हड़प ली थी, अब फिर तैयार है। जब पत्रकारों ने इन बातों से संबंधित प्रश्न किये तो जियाबाओं ने उल्टे ही इसे दोस्ती तोड़ने का कदम करार देकर पत्रकारों को ही नसीहत देने लगे।

कांग्रेस-संप्रग डकैतों और अपराधियों का गिरोह

2-जी के पहले व बाद में भी हजारों करोड़ के लेनदेन से घाटा
1998 से आईं सभी सेल कं. जालसाल
अंधी कमाई और चारों तरफ लूट

शीतकालीन संसद के सत्र में मचे 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन के घोटाले से भारतीय संसद गूंजती रही, भारतीय महालेखाकर व अंकेक्षण ने मात्र 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की ही अंकेक्षण रिपोर्ट पेश कर मात्र 1.76 लाख करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया, जबकि घोटाले तो 1998 से ही सेल कंपनियों के अस्तित्व में आने के साथ ही हजारों करोड़ में शुरू हो चुके थे। वो लाखों करोड़ जनता से लूट रहे थे और हजारों करोड़ बांट रहे थे, सबसे बड़ा घोटालेबाज थे रिलायंस के स्मार्ट और रिम, दूसरे नंबर पर थे। आरपीजी उर्फ आइडिया फिर बाजार में उतरा सुनील भारती मित्तल, टाटा व अन्य सभी बड़े जाने माने उद्योगपति, जिन्होंने न केवल जीपीआरएस में वरन डब्ल्यूएलएल अर्थात वायरलेस इन लोकल लूप, में लोकल लूप का लायसेंस लियिा और पूरे भारतवर्ष में भ्रष्ट शूकर निकंमा अर्थात भारत संचार निगम के साथ मिलकर पूरे देश में चलाया और पैसा लोकल लूप का चुकाते रहे और वर्तमान में भी चुका रहे हैं। सुनील भारती मित्तल ने तो एयरटेल और टचटेल में लोकल लूप और लैंड लाइन में भी कम से कम पूरे देश में रुपये 10000 करोड़ से ज्यादा घोटाले कर जनता को भी अनाप-शनाप बिलिंग में भी लूटा और भारत संचार निगम और संचार मंत्रालय को भी चंदन लगाया अरबों रुपये में, इस पर सीएजी अर्थात ......

कंट्रोलर आडीटर जनरल ऑफ इंडिया कागजी लेन-देन पर निगाह रखने और उसके अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने वाली, भारत के राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में चलने वाली यह संस्था है, जो स्वयं भी भारी भ्रष्ट", उनकी हर प्रदेश स्तर पर सभी विभागों के अंकेक्षण करने वाली प्रादेशिक संस्थाएं हैं, जो अपनी टीमों के माध्यम से सरकारी धन के उपयोग पर निगाह रखती हैं। ये इतनी भ्रष्ट और बिकाऊ होती है, कि इनकी टीम का मुखिया पहले ही अपनी वसूली की दरें बताकर, अधिकारी से तय कर लेता है और अपनी सीमायें निश्चित कर देता है। बाद में पूरी टीम बड़े-बड़े घोटालों, भ्रष्टाचारों और लूट को देखती है, और प्रश्नावली बनाती चलती है, जो दो तरह की होती है, जिसमें एक जो वास्तविक और बड़ी फंसाने वाली और दूसरी जिसमें उस अधिकारी का कुछ भी न बिगड़े और मामला कागजी जमा खर्च में सिमट जाये ओर ऐसी ऑडिट आपत्तियां वर्षों चला करती हैं। सभी शासकीय विभागों में कितने अधिकारियों, कर्मचारियों को इन ऑडिट आपत्तियों से उनकी पदोन्नतियां रुकी, कितनों की वेतन वृद्धियां रुकी, कितने नौकरी से निकाले गये या कितनों को निलंबित किया गया, जबकि हर विभाग में हर कदम-कदम भ्रष्टाचार राक्षस हर कदम-कदम पर नृत्य करता है। दूसरा प्रधानमंत्री को भी कई बार ईमेल के माध्यम से लिखा गया कि संसद में विधेयक लाकर तकनीकी परीक्षण और अंकेक्षण विभाग की स्थापना शीघ्र की जाये, जो हर नई योजना का तकनीकी आंकलन कर उसकी उपयोगिता, लागत,जनता को लाभ, शासन की लाभ-हानि को बारीकी से सुनिश्चित करे, चाहे वो स्पेक्ट्रम आवंटन हो, **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

वीकीलीक्स ने सिद्ध किया जो समय माया ने लिखा

अपनी सच्चाइयों से अमेरिका बौखलाया

भारत में वीकीलीक्स की साइट और समाचार सेंसर

अमेरिका वीकीलीक्स की सच्चाईयों जो अमेरिका की अपनी ही कारगुजारियों का आइना है, के लीकेज से भारी बौखलाया हुआ है। अमेरिकी प्रशासन अपने आप को दुनिया का रहनुमा और खुदा मानता है उसकी नजर में दुनिया की अन्य आबादी जानवर और धरती उसकी चारागाह हैं।

अमेरिका जो पूरी दुनिया की भिन्न-भिन्न देशों की धरती पर रहने वाले धूर्तों की जो अमेरिका में बस गये, किसंकर प्रजाति के धूर्त, मक्कार, चालाक और महा पेटुओं का गिरोह है, जो दुनिया के आम इंसान से तीन से छह गुना ज्यादा खाते हैं जिनके यहां हथियारों के उत्पादन के अतिरिक्त न तो खास कुछ धरती में पैदा होता है, न ही कोई प्राकृतिक संपदा का मालिक है, न ही कोई विशेष औद्योगिक उत्पादन है। उसकी धूर्तता और चालीकी का ही परिणाम है कि उसका डालर दुनिया की सर्वमान्य मुद्रा है। जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया चक्कर काटती है। समय माया इसकी सच्चाईयां अपने शैशव काल से वर्तमान तक अपने तीखे तेवरों में प्रगट करता आ रहा है।

विकीलीक्स डाट आरग के संचालकया मुख्य संपादक जुलियन असांजे ने हाल ही में इन अमेरिकी सच्चाईयों को दूर संचार तकनीकी के माध्यम से अमेरिकी साइटों और केवल पर सेंध लगाकर ऐसे लाखों दस्तावेज साइटों पर दुनिया की जनता के सामने प्रस्तुत कर दिये, जिससे पूरा अमेरिकी प्रशासन न केवल हिल उठा बल्कि पत्रकारिता के इस दैदीप्यमान नक्षत्र पर अपनी ......दृष्टि से विभिन्न आरोप लगाकर उसकी हत्या की योजना बना चुका है। इसके पूर्व में भी अमेरिकी सच्चाईयों के खुलासे और अमेरिका स्वीटजरलैंड की सरकार को खरीद कर उस पर अपनी नौकरानी के बलात्कार के आरोप लगवा कर स्वीटजरलैंड सरकार द्वारा उसे गिरफ्तार करने की योजना तैयार की थी, इस प्रकार एक सच प्रगट करने वाले पत्रकार को सताया गया, बेशक यह तो पत्रकारिता की व्यावसायिक प्राथमिकी है। फिर यह मनुष्य की स्वाभाविक मानसिकता है कि वह दूसरों का सच सुनना देखना चाहता है, परन्तु जब स्वयं का सच सामने आता है तो वह सच प्रगट करने वाले को धरती से विदा करने की नियत रखता है। ऐसा नहीं है, कि अमेरिका चाहे वह जुलियन असांजे हों या फीदेल कास्त्रो जो इसकी सच्चाइयां प्रगट करता है, वह किसी भी हद तक जाकर और गिरकर उसे दुनिया से विदा करने के लिय षड्यंत्र रचता ही है। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

सत्ता अर्थात भ्रष्टाचार, अवैध कृत्यों से वसूली और घोटाले

भारत में सत्ता का अर्थ जनहितार्थ, स्वयं कांटों पर चल कर, जनता का भविष्य संवारना नहीं वरन् सत्ता आते ही कुर्सी पाते ही जनहितों को त्याग, अपना हित साधना, कानूनों को तोड़ना, मरोड़ना या नये कानून बनाकर भ्रष्टाचार से धन कमाना, संपत्तियां एकत्रित करना हो चुका है।

सत्ता चाहे प्रधानमंत्री की हो या ग्राम पंचायत के सरपंच की। कैसे हाथ आई बारी से नोटों की क्यारियां बनाकर उससे कई गुना धन पैदा करना, बन चुका है। उसके लिये चाहे जनता को जानवर बनाकर जोतना हो, मरवाना हो, औषधि परीक्षण करवाकर 10-20 लाख लोगों को निपटाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न सत्ताधीशों को, न गुलाम मानसिकता की जनता को।

सत्ताधीश चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, यदि सबको पैसा मिल गया है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कानून बन जायेगें, जन हितों की धज्जियां उड़ायेंगे, जनता को रुलायेंगे। इसके विपरीत अपनी महानता के गुण गायेंगे, यदि पक्ष के लोगों को पैसा मिल गया और विपक्ष को उसका टुकड़ा नहीं मिला, तो फिर संसद को ठप्प करेंगे, जिद पर अड़ेंगे, जनता को भूल जायेंगे, सत्ताधीश फंस जायेंगे, तो घड़ियाली आंसु बहायेंगे, दिखायेंगे कि दुख हमें भी है, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम कमीशन डकार चुके हैं। जैसा कि वर्तमान में संसद में हो रहा है। फिर मार के नेता रूपी मंत्री प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर चुने गये सरपंचों तक वहां बैठे धूर्त सचिवों, जो इंडियन एक्यूसिंग सर्विस अधिकारी से लेकर सरपंचों के सचिव के रुप में बाबु के रूप में बैठा होता है। इन सब चुने हुए को शतरंज की बिसात पर नचाकर स्वयं 60% और इन चुने हुए को 40% का टुकड़ा डालकर पालतू श्वानों की तरह गले में पट्टा डालकर हांकता नचाता और चलाता रहता है। इसलिये यहां धन देकर उसके भुगतान से पूर्व भौतिक सत्यापन की जानबूझकर व्यवस्था नहीं की गई है। बेशक कागजी सत्यापन और उसके उपयोग के प्रमाणीकरण की तो कार्यादेश देने के पहले ही व्यवस्था हो जाती है।

चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वो सरपंच हो से लेकर पार्षद, विधायकों, सांसदों तक सब को मालूम है कि उनकी औकात और सत्ता के बल 5 वर्षों के लिये हैं, जितना जैसे जहां से लूट सको, हजम कर सको कर लो अन्यथा 5 वर्ष बाद पुनः सत्ता मिली, नहीं मिली कोई भरोसा नहीं, इसलिए सत्ता का अधिकतम उपयोग हर तरह से कर लिया जाना चाहिए अन्यथा 5 वर्ष बाद यह दिवास्वप्न देखना भी दूभर हो जायेगा। कैसा जनहित, कौन सा जन, जब तक तंत्र है, तो वसूली का मंत्र जपो, इसके लिये जो कुछ करना पड़े करो, इसलिये सरपंचों से लेकर प्रधानमंत्री तक, अपने ही बनाये कानूनों को तोड़ने मरोड़ने, पूंजीपतियों के हित साधन के लिये कानून बनाने, शासकीय संपत्तियों को अपना मानकर उसे गिरवी करने, बेचने, जनहित का सौदा करने, जमीनों को बेचने, नीलाम करने गिरवी रखने तक सब कुछ कर डालते हैं। जब पकड़े जाते हैं, तो गूंज जनता देखती सुनती है, से लेकर विदेशी कंपनियां तक अपने पैर जमाने, देश का दोहन करना, वैसे ही रणनीति तैयार कर इन सब खबरों को आधार बनाकर अपना खेल खेलते हैं।

इस देश को उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल से लेकर लाखों लघु उद्योगपतियों तक को अपना कार्य करवाने के लिये रिश्वत देकर ही अपना कारोबार किया है, दूध का धुला कोई नहीं। टाटा का साम्राज्य इस देश की भ्रष्टाचार की धारा में धन लुटाकर ही जनता को लूटा जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री स्वयं देश को परमाणु समझौते के नाम पर गिरवी कर मात्र कमीशन के लिये प्रदेशों के विद्युत मंडल बंद करवाकर निजीकरण पर उतारु है और उस प्रधानमंत्री कार्यालय में कदम का अंबर है, तो वो कैसे भ्रष्टाचार के राजा की तरफ अंगुली उठायेगा।

भोपाल में किसानों को महाजाम

भोपाल। 20 दिसंबर 2010 को राजधानी भोपाल में किसानों ने सुबह होते ही सारी सड़कें जाम कर दी। किसानों का यह आंदोलन न केवल ऐतिहासिक था। बल्कि शहरीयों के मुंह पर तमाचा है। सरकार के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जो बड़ी-बड़ी डींगे हांक रहे थे आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है कि जनता को और कम से कम किसानों को बड़े-बड़े विज्ञापनों और झूठी वाह-वाही से ज्यादा दिन भ्रमित नहीं किया जा सकता, धरा पर उतर कर बात करो। बिजली की कमी मप्र की वर्तमान सरकार जानबूझकर निजीकरण करने, निजी कंपनियों से मोटा पैसा उकारने जनता को लूटने और परेशान करने के दृष्टिकोण से कर रही है। इसलिए जानबूझकर एक तरफ सारणी की चारों विद्युत इकाइयों का उत्पादन ठप कर, बिगड़ने की बात कर बेचने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्रों से न केवल अपने हिस्से की वरना अनेक हिस्से की भी बिजली नहीं खरीद रही है। और अरबों रुपए रोज का कमीशन उकारने के लिए निजी कंपनियों से जिसमें टाटा, इस्सार, रिलायंस, जिंदल से महंगी बिजली की खरीद दिखा कर मोटा कमीशन उकार रही है। स्वाभिक है इससे किसानों को सिंचाई के सीजन में बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्हें इतना भारी आंदोलन करना पड़ा।

60% फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से नौकरी हथियाई है

जाति प्रमाण पत्र हैं या अंधों की रेवड़ी

सूचना के अधिकार में अधिकांश विभाग नहीं दे रहे जाति प्र.प. की कॉपी

म.प्र. लोक सूचना आयोग भी वैसा ही है, जैसो कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों के बारे में टिप्पणी की हैं यहां पर भी प्रदेशभर के भ्रष्टों को चुन-चुन कर सजाया जाता है; मुख्यमंत्रियों द्वारा स्वाभाविक है, यहां पर चुने जानेवाले प्रदेशभर के विभिन्न विभागों के अधिकारी कैसे होंगे, सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. को सूचना के अधिकारी में वर्तमान में प्रदेश में जितने भी आई.ए.एस. बनाम इंडियन एक्यूसिंग सर्विस अधिकारी जो जिलाधीश, आयुक्त, सचिव, प्रधान सचिव, एसडीएम या विभिन्न शासकीय विभागों, निगमों में बैठे हैं, उनकी जानकारी दी जाए, प्रदेश में राजधानी के सूत्रों से प्राप्त सूत्रों के अनुसार लगभग 15 आई.ए.एस. इस प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इसी प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा में यह आंकड़ा 100 से ऊपर है; जो न केवल फर्जी जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ ही जनम तिथियों में हेर-फेर के साथ प्रशासनिक पदों पर विराजे हैं औरा शूकरों की ये फौज जन,धन में दोनों हाथों सू लूटकर पलीता लगा रही हैं

जाति प्रमाण पत्रों में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा भी धड़ल्ले से जाति प्रमाण पत्र हाथ से लिखकर भी जारी किये गये हैं; जिन्हें स्वयं नहीं मालूम होता कि उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किये हैं। ऐसे अनेकों विभागों के जाति प्रमाण पत्र हमारे पास सूचना के अधिकार में प्राप्त हुये हैं।

म.प्र. लोक निर्माण विभाग में मुख्यालय का पत्र दिया गया पर वहां वेंटीलेटर पर सांस ले रहा महाधूर्त प्रमुख यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला जिसके बारे में पूर्व में भी समय माया के पाठक उसके भ्रष्टाचार और सफेद पोश डकैती के किस्से जो इस हरामखोर ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में रुपए 1200 करोड़ के बजट में डाली थी पढ़ चुके हैं। इससे जानकारी मांगी गई। पत्र न मिलने का बहाना बना दिया। अपील करने पर जवाब में लिखा दूसरा पत्र भेजें, दूसरा पत्र भेजा उसका कोई जवाब नहीं मिला। इंदौर के मुख्य अभियंता को पत्र दिया; जिससे मुख्य अभियंता एम.पी.सिंग ओर उसके छोटे भाई का.अ. सी.बी.सिंह का प्रमाण पत्र बिलासपुर जिले से बनाया गया, जबकि रहने वालो धार कुक्षी के हैं।

दूसरी ओर का.अ. ए.पी. राने, संभाग क्र. 2 इंदौर ने देने से मना कर दिया और भड़ में बोला, मैं नहीं दूंगा जो उखाड़ सको उखाड़ लेना, दूसरी ओर सर्विसबुक के पहले पन्ने की फोटो कॉपी में जन्म स्थान पर टुकड़ा चिपका था जिस पर जन्म दिनांक 06/08/1969 लिखा था। श्रीमान राने ने 1985 में हायर सेकण्डरी पास की अर्थात 6 वर्ष की आयु और 12वीं के 12 वर्ष, 18 वर्ष से पूर्व ही 12वीं पास कर ली जो स्पष्ट फर्जी है। हायर सेकण्डरी के अंक सूची की फोटो कॉपी भी नहीं मिली, फिर ग्वालियर में कैसे हायर सेकण्डरी होती है, सभी समझदार जानते हैं। यही हाल का.पं. यो.सि. बागोले झाबुआ संभाग का भी है। नवंबर 11 70 को जन्म और 1985 में 12वीं पास अर्थात साढ़े 14 वर्ष की उम्र में ही 12वीं पास, ढाई वर्ष की उम्र में ही पहली पढ़ने बैठ गये थे। सहायक अभियंता श्रीराम वर्मा (बि.व.यां.) धार, मूल निवासी रीवा, अनु. जाति कुम्हार, जबकि कुम्हार मात्र छतरपुर में ही अनु. जाति में आते हैं। यह प्रमाणपत्र भी फर्जी है। ऐसे ही देवास संभाग में अनीस खान पिता शहजादे सलीम खान जाति से मुसलमान मेवाली का जाति प्रमाण पत्र और अनिल कुमार शर्मा ने अपने आपको सुतार बताकर जाति प्रमाण पत्र लिया है। ये दोनों ही संदिग्ध हैं। इनकी जांच करवा कर नौकरी से हटाया जाना चाहिय। ऐसे फर्जी लोग अपनी मूल जाति को भी किसी भी जाति में बताकर फर्जी प्रमाण पत्र पैसे देकर प्राप्त कर सभी प्रकार के लाभ ले रहे हैं।

म.प्र. महिला बाल विकास विभाग जहां नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक केवल भ्रष्टाचार और झूठे और फर्जी कागजों पर सारी योजनाएं चलाकर पैसा हजम किया जाता है। ये जालसाजी का आलम देखिये कि श्रीअजमेरा ने जो पत्र जानकारी मांगने के लिए दिया गया उसे तो रद्दी की टोकरी में डालकर कहा गया कि पत्र ही नहीं मिला। इसके विपरीत हमारे पत्र लगाने के तुरंत बाद, संचानालय में बैठे किसी धूर्त और चालाक अधिकारी या कर्मचारदी ने वही आवेदन अपने किसी खास मिलने वाले दूसरे से लगवा दिया और उसकी जानकारी पूरे म.प्र. से इकट्ठी करवा कर उसे भेज दी गयी। जबकि हमारी अपील करने पर हमें केवल घोषित संपत्तियों का विवरण भेजकर इतिश्री कर ली गयी, जबकि यहां 40% से ज्यादा आरक्षित वर्ग में अधिकारी और कर्मचारी से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक सब फर्जी प्रमाण पत्रों की भरमार है।

यही हाल कृषि, राजस्व, म.प्र. जल संसाधन, पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, शिक्षा, मंडी, रेशम, उद्यानिकी, जिलाधीश कार्यालयों, जनपद पंचायतों, नगर निगमों, पालिकाओं विद्युत मंडल, वाणिज्य कर, आबकारी,पुलिस विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति, खाद्य एवं औषधि, स्वास्थ्य विभाग, न्याय पालिका, नापतौल, मत्स्य, सहकारिता, ऐसे सभी विभागों में 40% अधिकारी और कर्मचारी फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरियां कर रहे हैं।

होटल सायाजी में कार चोरी-

सिद्ध करती है, होटल प्रबंधन के आतंकवादियों से संबंध

उच्च स्तरीय आपराधिक गतिविधियों का अड्डा

इंदौर में होटल सायाजी अपने पार्किंग में, क्लब, रसोई, के निर्माण के चलते पूर्व से ही सुर्खियों में हैं प्रशासनिक अधिकारियों को मुफ्त में घर के बाहर, होटल में घर जैसी सुविधाएं देने, मंत्रियों, नेताओं की आवभगत करने होटल के वाणिज्यिक कर में छूट पाने आदि से पूर्व में ही सुर्खियों में रहा है। समाचार पत्रों में झूठी खबरें छपवाकर कि पार्किंग में बने निर्माण तोड़ दिये गये हैं, जबकि वहां सब यथावत है; से जनसामान्य अंदाजा लगा सकता है कि मुफ्तखोर अधिकारी चंद सुविधाओं का लाभ उठाकर होटल प्रबंधन के सामने कैसी दुम हिलाते हैं।

पाठकों को याद होगा नववर्ष की पूव्र संध्या पर आयोजित नग्न नृत्यों पर जब हिन्दू संगठनों ने संस्कृति के पक्ष में रोकने के लिए आंदोलन किया तो उस समय के तात्कालीन जिलाधीश विवेक अग्रवाल ने कड़ी पुलिस व्यवस्था कर स्वयं घोड़े पर बैठकर, उस हरामखोर ने उन राष्ट्रभक्तों पर लट्ठ बरसाये थे; जब उसकी गहराई में गये तो ज्ञात हुआ कि उसके सारे रिश्तेदारों, मिलने-जुलने वालों को होटल सयाजी मुफ्त में सारी सुविधाएं प्रदान करता था। दूसरी ओर म.प्र. खाद्य एवं औषधि विभाग का वह इस होटल का .....निरीक्षक हर महीने रुपए 25000 प्राप्त कर इस होटल की केवल जी हजूरी करता है; वरना किसी भी खाद्य निरीक्षक को भी वहां नमूना लेने के लिये नहीं फटकने देता और गलती से गाहे-बगाहे कोई फटकने की हिम्मत भी कर ले, तो उस समय का तात्कालीन जिलाधीश विवेक अग्रवाल और अब राघवेन्द्र सिंग के ऐसे खाद्य निरीक्षकों को नमूने लेने से न केवल रोकते हैं वरना उन्हें हड़काते भी हैं; क्योंकि उस होटल की सेवायें लेने में ये मुफ्तखोर अपनी शान और रुतबे का प्रभाव समझते हैं। यही हाल श्रम विभाग के निरीक्षकों और म.प्र. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि के निरीक्षकों को आदि सभी को महीना मिलता हैद्ध तो ये सारे भुखेरे कैसे कोई यहां के प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करेगा। दूसरी ओर इस देश में जो जितना बड़ा, वो उतना बड़ा भ्रष्ट, टैक्स चोर, रिश्वतखोर, सफेद पोश डकैत है। अपराधी, कुकर्मी, जालसाल भी है। वही ऐसी काली कमाई ही इन होटलों में खर्च कर सकता है। चाहे फिर वह उद्योगपति, कॉलोनाइजन, भूमाफिया, शिक्षा माफिया, उसमें फिर चाहे मुकेश, अनिल अंबानी हो, सुनील मित्तल, वेदांता का अनिल अग्रवाल हो, या नेताओं में कमलनाथ, चीटर .....जयरामरमेश, कैलाश विजयवर्गीय, राघवजी, अजय विश्नोई ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, अब होटल में ठहरेंगे तो प्रबंधन से संबंध बन ही जायेंगे।

अब सवाल उठता है कि जिस मुशर्रफ अली ने 8 नवम्बर को होटल के काउंटर से चाबी लेकर स्वीफ्ट कार एमपी-09-एचई-0002 चुराकर राहत को दे दी थी, आखिर मुशर्रफ अली ने जिस सायाजी होटल में नौकरी की, उसके पहले होटल प्रबंधन ने उसकी छानबीन की थी; क्या पुलिस को सूचना दी थी; अगर नहीं तो होटल प्रबंधन से पूछताछ क्यों नहीं की गई? किस आका के इशारे पर उसे बिना पूछताछ के ही और पुलिस को सूचना दिये बिना नौकरी पर क्यों ओर कैसे रख लिया अर्थात होटल प्रबंधन भी आतंकियों से मिला हुआ है। उनके इशारों पर ही इंदौर में ऐसे आतंकवादियों काश्मीरियों और पाकिस्तानियों को इंदौर जैसे शहर में चुपचाप नौकरी पर रखकर राष्ट्र की सुरक्षा को खोखला किया जा रहा है। आखिर एटीएस होटल प्रबंधन के बड़े लोगों से संबंधों के चलते उसे क्यों छोड़ दिया, जबकि वो भी इस काण्ड में सीधे जुड़े हुये हैं। होटल प्रबंधन से क्या एटीएस ने सभी कर्मचारियों की जानकारी निकलवाई कौन कहां से आया और कब से अपनी पहचान बदलकर नौकरी कर रहा है। बेशक एटीएस पर बड़े-बड़े आई.ए.एस., आई.पी.एस., मंत्रियों, नेताओं का दबाव आ रहा होगा और ऐसी छानबीन करने पर और आयेगा; बाहर से आने वाली डांसिंग गर्ल्स व उनकी टीम, होटल के स्थायी ग्राहकों की सूची, होटल में पूर्व में कितनी कारें चोरी गयीं, जिम ट्रेनर ने महिला ग्राहकों की प्रशिक्षण के दौरान फिल्में तो नहीं बनाई इन सबकी भी जांच होनी चाहिये। मामला मात्र कार चोरी का ही नहीं वरना वहां के कर्मचारियों के माध्यम से चल रहे नेटवर्क का है। सरकारी अधिकारियों को सुविधाएं देकर कौन-कौन सी सुविधाओं का लाभ उठाया गया है अगर इसकी खोजबीन की जाए तो भोपाल से दिल्ली से आने वाले हर अधिकारी, नेता, मंत्री जो इस होटल में ठहरता है, सब लपेटे में आ जायेंगे और सरकारे मुंह दिखाने लायक नहीं रह जायेंगी। स्थिति यहां तक पहुंचेगी। वैसे भी पूरा देश राम भरोसे से धर्मशाला की तरह चल रहा है, क्योंकि सत्ता और सरकार में भ्रष्टों की फौज बैठी है।

अपनी सच्चाइयों से अमेरिका बौखलाया

प्रथम पृष्ठ का शेष

समय माया ने अपने शैशव काल से ही अमेरिकी मक्कारियों, बत्तमीजियों और गुण्डागर्दियों के खिलाफ सदा से ही अवाज मुखर की है। बेशक विकीलीक्स केवल वह लीक करया जा रहा है जो अमेरिकी दस्तावेजों में अमेरिका ने किया है, इसके विपरीत समय माया ने अमेरिकी इतिहास और वर्तमान के अध्ययन से निकाले निष्कर्षों के आधार पर वह सब भी प्रगट किया है, जिसके बारे में दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकार, टीवी न्यूज चैनल, विश्व के बड़े-बड़े समाचार कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसे दुनिया में आने वाली हर सुनामी बम के विस्फोटों से लाई जाती है। 26 दिसम्बर, 04 को दक्षिण एशिया के जकार्ता, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि में आई सुनामी अमेरिका द्वारा समुद्र में किये गये भीषण नाभिकीय और परमाणु बमों के परीक्षण का परिणाम थी। समय माया की उस समय ज्यासिटीज पर करप्शन 2 इंडिया के नाम से चलने वाली साइट पर इस बात का खुलासा 27 दिसम्बर, 04 को रात्रि 12:30 पर दिया गया था, जिसे बाद में वाइकीपिडिया के शबदकोष में भी शामिल कर लिया गया। इसी प्रकार अमेरिका का चांद और मंगल पर पानी की झूठी नौटंकी का पर्दाफाश भी समय माया ने किया और बताया कि जिस गृह पर तरलता वहां बादल और जहां बांदल वहां जीवन, जबकि चंद्रमा व मंगल पर बादल ही नहीं हैं तो वहां पानी जैसी तरलता नहीं है और तरलता नहीं है तो जीवन असंभव है, जो वर्तमान में चल रही समय माया. काम की साइट पर पुराने समाचार पत्रों में देखा जा सकता है। विकीलीक्स को इससे संबंधित दस्तावेजों को अभी साइट पर डालकर यह सच उजागर करना बाकी है।

अमेरिकी प्रशासन, विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, व अन्य असांजे द्वारा प्रगट किये जा रहे सच से न केवल बौखलाए हुए हैं वरन असांजे को कानूनी तरीके से या अपनी जासूस एजेंसियों के माध्यम से ठिकाने लगाने के लिए बेताब हैं। भारत में गूगल उसकी सीधी साइट नहीं खोल रहा है। साथ ही भारत से संबंधित सारे के सारे तथ्य गायब हैं अर्थात अमेरिकी इशारे पर सोनिया ने अपने पिट्ठू सरकार मनमोहन से कहकर सारे तथ्यों को गायब करवा दिया गया है। या सीधी भाषा में विकीलीक्स साइट को सेंसर किया जा रहा है। ताकि चलते लोकसभा के सत्र में अभी नया कोई बखेड़ा खड़ा न हो जाएं इसके साथ ही दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक भारतीय समाचार पत्र भी इन राज्यों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। या नहीं कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि विकीलीक्स के अमेरिकी जाल साजियों और भारत के साथ किये गये व्यवहार को पूर्णतः भारत में सेंसर कर रहा है। यदि सच्चाईयां जो भरत के बारे में ब्रिटेन के समाचार पत्रों से छनकर भारतीय समाचार पत्रों ने 26/11 के बारे में छापी है। भारत के सत्ताधारियों को,जो कि महाबेशर्म, निकम्मे, रिश्वतखोर, जालसाज हैं लोकसभा के गलियारों में मुंह उठाकर चलना नहीं छोड़ती। विकीलीक्स ने 26/11 के बारे में जो प्रगट किया है; उसमें अमेरिका की भूमिका और हेडली से भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ न करना भी अमेरिका के साथ भारतीय सत्ताधारियों के चरित्र को देशद्रोही की श्रेणी में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। गृह मंत्रालय और भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी थी कि मुंबई में हमला हो सकता है। जिसकी चर्चायें पूर्व में भी भारतीय प्रचार माध्यमों ने प्रसारित व प्रकाशित कर दी थीं। यही कारण है कि भारत के सत्ताधीश विकीलीक्स के लीकेज पर मन से धन खर्च करके कांक्रीट की परतें चढ़ा रहे हैं। भारत सरकार के कांग्रेसी धूर्तों ने करोड़ों डालर देकर गूगल जैसी साइट को खरीदा, भारत में गूगल न तो उसकी साइट खोलता है और ध्यान बांटने के लिये उल्टे सीधे खोज परिणाम दिखाता है। इन कांग्रेसी डकैतों को डर है कि ये गुलाम मानसिकता के धूर्तों ने अमेरिका की हर ज्यादती के सामने न केवल घूटने टेके हैं बल्कि देश को गिरवी करने और सोनिया विदेशी एजेंट के इशारे पर अरबों डालकर का लाभ पहुंचाया जा रहा है हर वर्ष।

इसके विपरीत अमेरिका ही है,जो एक तरफ तो पाक को उसके नापाक इरादों की आईएसआई को आर्थिक सहायता देकर उसके आतंकवादियों को धन, आर्थिक सहायता देकर भारत विरोधी षड्यंत्रों को अंजाम देता है। विकीलीक्स में इन सब बातों के मय सबूतों के खुलासे किये गये हैं। इसलिए भारत में विकीलीक्स पर प्रतिबंध लगा रखा है।

सत्ताधीश चाहें तो अमेरिका के हों, भारत के, पाक के या दुनिया के अन्य देशों के जनहितों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, पैसा एकत्रित करना और अपनी सल्तनत खड़ी करना ही सत्ताधीश का उद्देश्य होता है; जब जुलियन असांजे जैसा व्यक्ति उन्हें आइना दिखाता है तो मिर्ची लगती है। यह मानवीय स्वाभाविक प्रकृति है।

म.प्र. वाणिज्य कर सभी के क्षेत्रों में जाकर करनी चाहिए वसूली

कर वसूली में व्यापारी को छूट- जनता से लूट

इंदौर। म.प्र. के वाणिज्य कर मुख्यालय में और भोपाल के वित्त मंत्रालय में वाणिज्य कर या विक्रय कर की वसूली में हुये भारी फेर-बदल से नाराज व्यापारियों और उनके माल का परिवहन करने वालों में ट्रांसपोर्टर्स ने पकड़-धकड़ से रूष्ट होकर 22/22/10 को हड़ताल कर दी है। करीब इंदौर में ही 5000 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स की वाणिज्य कर की चारी को बारीकी से रोकने के लिए पहल क्या शुरू की और ट्रकों को पकड़ना शुरू करते ही वे सब इस व्यवस्था को रोकने के लिए दबाव बनाने की नियत से ही हड़ताल पर गये हैं। बेशक वाणिज्यक आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने देर से ही, पर सही कदम उठाया, क्योंकि व्यापारी दोनों तरफ से वाणिज्य कर की चोरी को पूरी कर रहा था। वास्तविकता में वाणिज्य कर पूरे प्रदेश के कुल विक्रय की वाणिज्य कर आय का 30% हिस्सा ही वसूल पाता है। 10 से 20% कर्मचारी, निरीक्षक, सहायक कराधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, सहायक उपायुक्त, आडिट, और एंटी इविजन ब्यूरो डकार जाता है। बाकी 50 से 60% वाणिज्य कर व्यापारी जनता से तो पूरा वसूलता है और स्वयं हजम कर लेता है। यही हाल सभी करों, आबकारी, कस्टम एण्ड एक्साइज और आयकर का भी होता है।

म.प्र. वाणिज्यकर वैसे तो पूरे विभाग का मूल उद्देश्य ही कर वसूलना और कर चोरी रोकना है। परन्तु आयुक्त पी.के. दास ने यह ठेका एंटी इविजन ब्यूरो विंग का गठन करके उसे सौंप दिया था, कि आठों विंग पूरे म.प्र. से ट्रकों को रोक कर, छापे मारकर टेक्स चोरी रोकेगी, परन्तु इनमें से अधिकांश ने ट्रांसपोर्टर्स से, बड़ी कंपनियों, बड़े दो नंबर का धंधा करने वालों से महीना बांध लिया था, जिन्होंने महीना देना स्वीकार नहीं किया था उनके ही ट्रक पकड़े जाते थे, एंटी इबेजन के चेतक चेम्बर स्थित ए और बी विंग की नाक के नीचे पेट्रोल पंप पर ही बसों पर 5'-5' ऊपर सामान लादकर ले जाया जाता ाि और ये आंख बंदकर देखते रहते थे, इसके चलते पूरे विभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारियों की आंख की किरकिरी बन गई। एंटीइविजन ब्यूरो विंग, मोटे अनुमान के अनुसार और विभागीय विश्वस्त सूत्रों से सूचना के अनुसार इंदौर की ए और बी विंग अकेले ट्रांसपोर्टर्स से ही पिदले तीन वर्षों से रु. 20 करोड़ प्रति माह प्रति विंग वसूली होती थी। ऊपर से पूरे पश्चिमी म.प्र. जो तीन राज्यों की सीमाओं, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं से घिरा है, से लगभग प्रतिदिन 1000 ट्रकों से ज्यादा म.प्र. की सीमा में प्रवेश करते थे सभी नाकों पर जिसमें पिटोल, सेंधवा, बुरहानपुर, डोंगर गांव, सोयत, ढावला जोड़ आदि पर वहीं लेन-देन हो जाता था। अब जबकि एंटी इविजन ब्यूरो की शक्तिाां सभी निरीक्षकों और सहायक कर अधिकारियों को दे दी गई हैं, जिससे अचानक नवम्बर के महीने में 30% की टेक्स बढ़ोतरी होने से एक तरफ एंटीइवेजन ब्यूरो की कारगुजारियां सामने आ गई हैं। यहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी बौखला गये हैं, क्योंकि उनकी टेक्स चोरी, माल खरीदी और बिक्री का हेर-फेर भी सामने आने से सच्चाईयां उजागर हो रही हैं। इसलिये तो निरीक्षक राज को हड़ताल करके, सरकार पर दबाव बनाकर इसे बंद करवाना चाहते हैं। एक तरफ तो व्यापारी टेक्स चोरी कर सरकार को प्रतिवर्ष रु. 10000 करोड़ रु. से ज्यादा का चूना लगाता है। दूसरी तरफ जनता की जेब से पूरा वसूला जाता है। वर्तमान में जो वाणिज्य कर म.प्र. शासन को मिलता है, उसमें मुख्य रूप से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ बड़ी कार्पोरेश

सूचना के अधिकार में जानकारी देने में सारा तंत्र बेईमान

कंपन का 50% से ज्यादा हिस्सा होता है, जबकि वास्तविकता में मात्र कुल वाणिज्य कर का 30% ही शासन वसूल कर पाता है। यह बात शासन भी जानता है। इसके विपरीत पूंजीपतियों और व्यापारियों की इस पार्टी ने रु. 4 करोड़ से कम के व्यापारिक लेन-देन करने वालों को खुली लेन-देन स्व निर्धारण कर इन सबकी भनक लगते ही ठीक दीपावली के समय नवम्बर 1 से 30 नवम्बर, 10 तक वाणिज्य कर आयुक्त शैलेन्द्र सिंग ने पूरे म.प्र. की एंटी इवेजन ब्यूरो को छापे और ट्रक पकड़ने की कार्यवाही से वंचित कर पूरे म.प्र. के 76 वृत्तों के निरीक्षकों और सहायक वाणिज्यकर अधिकारियों से करवाया जिसमें 30% की आई वृद्धि सिद्ध करती है कि आखिर रु. 50 लाख तक की रिश्वत देकर क्यों उपायुक्तों ने यहां पद स्थापनायें करवाई, दूसरा वाणिज्य कर कार्यालय की टेबल पर बैठकर नहीं वसूला जा सकता, तीसरा व्यापारी को कितनी भी छूट दे दी जाए वह कर चोरी से बाज नहीं आएगा, चौथा आखिर नाकों पर बैठे वाला वाणिज्य कर का स्टॉफ खुले में लेन-देन कर आंख बंद कर व्यापारियों को कर चोरी की छूट दे रहा है। पांचवा व्यापारी चाहे एकल हो, साझेदारी फर्म हो, निजी सार्वजनिक बड़ी-बड़ी कार्पोरेट कंपनियां सभी कर चोरी को व्यावसाय का धर्म मानते हैं। छठा-व्यापरी, फर्मे, कंपनियां ग्राहक से तो सभी प्रकार का कर वसूल लेते हैं, भले ही सरकार को चुकायें, न चकायें।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है,आखिर कौन ईमानदार है। हमारी नजर में सभी बेईमान हैं, चाहें आयुक्त शैलेन्द्र सिंग हों, या एंटी इवेजन के उपायुक्त, सहायक आयुक्त, कराधिकारी, सहायक कराधिकारी, निरीक्षक, बाबू या चपरासी, हो साकता है एक, दो ईमानदार हों, परन्तु वो बेचारे इन बेईमानों के बीच में मुंह छिपाकर ऐन-केन-प्रकारेण हाथ जोड़कर नौकरी कर रहे होंगे, परन्तु सबके निशाने पर होंगे।

श्री अजमेरा ने सूचना के अधिकार में जून, 10 में जानकारी मांगी थी। सभी आरक्षित वर्ग के निरीक्षकों से लेकर आयुक्त तक सभी के जाति व मूल निवासी प्रमाण दिये जाने पर सुनवाई नहीं हुई। अपील दी गई, अपील में निर्णय दिया गया कि आवेदन को जानकारी निःशुल्क दी जाए, लोक सूचना अधिकारी का कहना है, म.प्र. लोकसेवा आयोग सारे प्रमाण पत्रों की कांपियां रख लेता है हम कहां से दें। कर की वसूली पर छूट देकर व्यापारियों को दोहरा लाभ पहुंचाया, जिसमें कम से कम वाणिज्य कर विभाग को रु. 2000 करोड़ से ज्यादा का सकल नुकसान हुआ, जबकि रु. 4 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन करने वालों के प्रकरण सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी देखते जिसमें एकल और पार्टनरशिप फर्मों ने तो मात्र कुल लेन-देन का 10 से 25% एक नंबर में दिखाकर कर दायित्वों से बचाकर मुक्ति पा ली, परन्तु निजी, सार्वजनिक और शासकीय उपक्रमों को कर भुगतान करना पड़ा, जिसकी सत्यता नवम्बर माह में छापे मारने, ट्रकों को पकड़कर वसूलने के निरीक्षकों और सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों को दिये अधिकारों और उससे प्राप्त 30% से ज्यादा कर की वसूली से सिद्ध होती है। जो यह भी स्पष्ट करता है कि एंटी इवेजन ब्यूरो मासिक वसूली का खुला अड्डा बन चुकी थी। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सितम्बर, अक्टूबर, 10 में एंटी इवेजन ब्यूरो में उपायुक्तों की नई स्थानान्तरण सूची में स्थान पाने के लिए म.प्र. के वित्त मंत्री राघवजी भले ही ईमानदारी का चोला ओढ़े होने की नौटंकी करें परन्तु उनकी पुत्री ज्योति शाह, नगर पालिका अध्यक्ष विदिशा ने इन नियुक्ति में, वाणिज्य कर अधिकारी रिघारिया के माध्यम से खुले में लाखों का लेन-देन कर उपायुक्तों को एंटी इवेजन में स्थानान्तरण कर रेवड़ियां बांटी। विभागीय विश्वस्त सूत्रों के अनुसार डीसी करोड़िया ने रु. 50 लाख इंदौर बी विंग, डीसी रमेश चौहान जबलपुर रु. 35 लाख, डीसी मिरा कुमार सतना ने म. 32 लाख, डीसी डी आर शर्मा रु. 30 लाख भोपाल के लिये,डीसी आईपी जैन रु. 35 लाख ग्वालियर के लिये, डीसी भरावी ने रु. 50 लाख ए विंग के लिये, डीसी जे.एस. गुप्ता रु. 25 लाख छिन्दवाड़ा के लिये भुगतान किये, जब उन्हें उनकी मनचाही एंटीइवेजन में नियुक्तियां मिली, इंदौर के वृत्त 9 के लिये रु. 10 लाख, सहायक आयुक्त आनंद भार्गव ने भी अवर सहायक आयुक्त अधिकारी के माध्यम से उनकी बिटिया को भुगतान किये।

जबकि हर आवेदक चाहे वह किसी पद पर नियुक्ति उपस्थित के समय जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अंक सूचियों की छायाप्रतियां मूल के साथ प्रस्तुत करता है जो सत्यापित करके लौटा दी जाती है। इसके विपरीत मुख्यालय कहता है, लोकसेवा आयोग ने नहीं दी और देने से साफ बचना चाहता है। जबकि डी.सी. मीना जो सागर में पदस्थ हैं, का प्रमाण पत्र फर्जी है। ऐसे ही आरक्षित में नियुक्ति पाये 40% अधिकारी और कर्मचारी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जमे बैठे हैं, जो न केवल सामान्य का वरन आरक्षित वर्ग के लोगों का भी हक मार रहे हैं। जब मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी से कहा गया कि सर्विस बुक के पहले पन्ने की फोटो कॉपी दे दें, तो उनका कहना था दूसरा आवेदन पत्र दें हमारे पास वैसे सर्विस बुक भी नहीं है। अर्थात बेईमान सब ही हैं। एक बेईमान दूसरे बेईमान को बचाता है सो ये सब एक दूसरे की ढाक रहे हैं।

कांग्रेस-संप्रग डकैतों और अपराधियों का गिरोह

प्रथम पृष्ठ का शेष

पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण, मिसाइल, वायुयान जहाज हो, इसके विपरीत समय माया की ये आवाज को वर्षों से अनदेखा कर जनता के खून पसीने की कमाई की लूट और राष्ट्र के धन की बर्बादी की जा रही है।

भारत संचार निगम लिमिटेड जो देश की सबसे पुरानी संचार कंपनी है यहां बैठे सुपरवाइजन से लेकर सहायक संभागीय उप प्रबंधक, प्रबंधक, उप महाप्रबंधक से लेकर पूरे देश का प्रबंध संचालक और अध्यक्ष तक हर वर्ष मिलकर अरबों रुपये की जालसाजियां करते आ रहे हैं। पिदले शताब्दी से वर्तमान तक, पर कोई तकनीकी परीक्षण और अंकेक्षण के अनुसार में किसी को भी अभी तक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सजायें नहीं मिलीं, जबकि इस संचार मंत्रालय में चाहे वो एमटीएनएल, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड हो, कदम पर खरीदी कार्यों में 25 से 40% तक खुलकर कमीशन डकारा जाता रहा है। पर केग के ऑडिटर्स कुछ भी खास नहीं कर पाए।

वर्तमान में केग की जो रिपोर्ट संसद में हंगामे का आधार बनी और केग के आडिटर्स ने 3 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी और आवंटन की तुलना में, 2 जी स्पेक्ट्रम में अपनाई गई प्रक्रिया की गई चालबाजियों से अनुमान लगाकर रु. 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा प्राप्त किया, जबकि कारोबार का प्रारंभ 1985 से ही शुरू हो चुका था। यदि जांच वहां से शुरू की जाती तो चारों बड़े खिलाड़ी भारती का एयरटेल, टयटैल, बिरला का आरपीजी आइडिया, टाटा का, रिलायंस का रिलायंस स्मार्ट और रिम पर ही रु. 10 से 20 लाख करोड़ के घोटाले सामने आते और जनता के साथ जो पूरे देश में 80 करोड़ मोबाइलधारी और 40 करोड़ से ज्यादा बीएसएनएल, भारती, रिलायंस, टाटा के लैंड लाइंस फोनों पर हर मिनिट जनता से रु. 1 अरब से ज्यादा काल ड्रापिंग, मिस काल, कालर टोन, इन कमिंग, आडट गोइंग सांग्स टोन, अनाप-शनाप बिलों की और प्रीपेड में वसूली की जा रही है और कमाई की जा रही है उसको भी रोका जा सकता था, पर न तो इसको रोका जा रहा है और जनता से हर मिनिट चौबीसों घंटे अरबों रु. की अवैध वसूली की जाने की संचार मंत्रालय को भी जानकारी होने के बाद भी कोई ठोस कदम उठाकर जनता के साथ की जा रही लूट को भी बंद करना, वर्तमान और भविष्य में भी नहीं चाहता है, जहां तक दूर संचार नियामक आयोग का सवाल है, तो आयोग कितनी कानूनी औकात होती है उतनी औकात से काम करके वह भी वसूली में जुटा है।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. लोक स्व-स्वार्थ यांत्रिकीय विभाग, मुख्यमंत्री-मंत्री, प्रधान सचिव सबको करोड़ों में बंटता है

भ्रष्टों, जालसाजों, अपराधियों का बोलबाला

म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभगा वास्तविकता में लोक स्व-स्वार्थ यांत्रिकीय विभाग बन चुका है। जहां चारों तरफ भ्रष्ट, जालसाल और आपराधिक प्रवृत्ति के इंजीनियरों का बोलबाला है। इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि प्रमुख अभियंता के प्रभार में बैठे प्रमुख अभियंता जी.एस. डामोर पर अपनी पत्नी की हत्या, जिसे पैसे खर्च कर आत्महत्या में बदल दिया गया था, के साथ में चार हतओं के आरोपों से जालसीपूर्ण तरीके से दिये गये साक्ष्यों और धन के बल पर बरी हो चुके, डामोर के विरुद्ध विभागीय भी दो चार करोड़ रुपऐ के घोटालों की जांचें लोकायुक्त में उच्च न्यायालय के स्थगन से वर्षो से लंबित पड़ी होने के बाद भी यह अपराधी प्रमुख अभियंता का प्रभार देख रहा है, जबकि प्रमुख अभियंता का पद सामान्य जाति वर्ग के लिये आरक्षित है। इसे विपरीत प्रधान सचिव आर.के. स्वाई, सचिव श्रीवास्तव, स्वंय मंत्री बिसेन भी जान बूझकर चूंकि करोड़ों रुपए की रिश्वत डकार चुके हैं इसलिए मामले को लंबा खींच रहे हैं, ताकि यह पद पर रहकर पूरे म.प्र. के लोक स्वार्थ यांत्रिकीय जहां सितंबर से लेकर मार्च के वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक विभिन्न योजनाओं जिनमें केंद्र व राज्य का रुपए 1200 से 1500 करोड़ के बजट में से रुपए 100 से 300 करोड़ रुपए की बंदर बांट कर लूटपाट और भ्रष्टाचार किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज मंचों से और विज्ञापनों में अपने आपको भले ही साफ-सुधरा जन हितकारी सिद्ध करता हो, परन्तु हर विभाग में बैठे भारी जालसाजों, भ्रष्टों और अपराधियों को पालकर, उनसे धन बंटोरना इसका भी शगल बन चुका है; फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में ही ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट, जालसाज, आई.ए.एस. के हरामखोर अधिकारियों का जमावड़ा हो, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो आपराधिक और भ्रष्ट डामोर जैसे अधिकारी पर न्यायालयों में मुकदमा चलवायें। आखिर जब इस अधिकारी पर 5 हत्याओं में बरी होने के प्रकरण हैं तो कम से कम सीआईडी जांच करवा कर जांच क्यों नहीं करवाई जाती; अन्यथा केंद्रीय जांच ब्यूरो में रिपोर्ट जाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मुद्दा उठने पर न केवल यह प्रभारी प्रमुख अभियंता वरन सरकार भी लपेटे में आयेगी। बेशक इसने चारों तरफ सभी संभागों में जहां बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सभी जालसाल, निकम्मे अधिकारियों को बैठा दिया है जैसे इंदौर वृत्त में सरदारपुर संभाग जहां महाभ्रष्ट सूर्यवंशी बैठा है, जिसने इस जालसाज डामोर के कहने पर रु. 3.89 करोड़ की अनावश्यक कस्टम व एक्साइज ड्यूटी का भुगतान भोपाल की इलेक्ट्रोथर्म जो कि एन.के. जैन की है को रु. 50 लाखका कमीशन

पर म.प्र. महालेखाकर के अंकेक्षकों ने भी न केवल आपत्ति उठाई थी वरन् भुगतान रोकने के लिए भी लिखा था, पर उसमें डामोर ने रु. 2.50 करोड़ से ज्यादा डकार कर भुगतान करवा दिया था, उस काण्ड में कार्यालय यांत्रिकी सूर्यवंशी को भी जांच होकर आरोप पत्र मिलना चाहिए; जबकि वह आरक्षण से अधीक्षण यंत्री बनने की तैयारी में है। अकेले डामोर ने ही पश्चिमी क्षेत्र का मुख्य अभियंता हरते हुए लगभग रुपए 1000 करोड़ की हर वर्ष खरीदी के आदेश जारी किये, जिनके भुगतान कार्यपालन अभियंताओं के माध्यम से 25 से 40% कमीशन डकार कर धड़ल्ले से किये गये, जिसमें इसका 10% हिस्सा था, पूर्व प्रमुख अभियंता एस.के. सक्सेना भी इसकी जांच के लिए लिखा, परन्तु न तो मुख्यमंत्री कार्यालय से, न ही मंत्री प्रधान सचिव, सचिव के कार्यालय से जांच कार्य करवाने के लिए लिखा, क्योंकि सारे भ्रष्ट शूकरों ने करोड़ों में माल हजम किया था।

प्रमुख अभियंता प्रभार संभाल रहे इस आपराधिक डकैत डामोर ने जो काम करने वाले समझदार अधिकारी थे, उन्हें तीन वर्ष होने से पहले ही न निकंमा बनाने की साजिश रची, तो दूसरी तरफ राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाने इंदौर वृत्त में भ्रष्ट सोलंकी को अधीक्षण यंत्री बनाकर इंदौर में, ग्रामीण में अहिरवार को कार्यालय यंत्री बनाकर, देवास में कार्यालय यंत्री राजेश जोशी, जो इसके इशारे पर नाच सके, जितना मांगे इसको धन दे सके। उल्टे-सीधे आंख मींच कर भुगतान करे, वैसे तो नर्मदा इंदौर में भी कार्यालय अभियंता धर्मेन्द्र वर्मा, से लेकर पूरे इंदौर झोन में बड़े भ्रष्ट और निकंमों को बैठाया ताकि वो जैसा इन श्वानों को नचाये और कानून को बलाये ताक रखकर भ्रष्टाचार करे।

30 सितंबर 10 को प्रमुख अभियंता पद से एस.के. सक्सेना के सेवा निवृत्ति के बाद ये तत्काल कार्यभार संभालने पहुंच गया था। उसके पहले पूरा भार ग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में रुपए 10 करोड़, रुपए 5 करोड़ मंत्री, रु. 3 करोड़ आर.के. स्वाई को भी भेंट कर दिये थे, सारे भ्रष्ट इसे पूर्ण प्रभार देने के लिए तैयार भी हैं। इसीलिए जानबूझकर अगले मुख्य अभियंताओं की स्क्रीनिंग होने के बाद भी अभी तक किसी को प्रमुख अभियंता का प्रभार नहीं दिया गया, जबकि इसकी घुसपैठ बनाने के लिए इसकी पदोन्नति प्राप्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी सूरज रोकड़े अब डामोर भी तन, मन, धन से जुटी हुई है, जिसे न बात करने और काम करने का तरीका आता है। इन हरामखोरों प्रधान सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता वर्तमान में मुख्य अभियंता इंदौर संकुले, उनका अधीक्षण यंत्री, भ्रष्ट जालसाज अजय दाहिया जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर केवल नौकरी कर रहा है, वरन आम सामान्य वर्ग के इंजीनियरों को धकेल कर अधीक्षण यंत्री बना हुआ है, जिसने अपने इंदौर संभाग के कार्यकाल में करीब रुपए 50 करोड़ से ज्यादा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में डकार कर अपनी सांवेर रोड के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री खोले स्तरहीन पाइप बना कर लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग को भी आपूर्ति कर रहा है, ये सारे हरामखोर जालसाज आखिर सूचना के अधिकार में कैसे देंगे जानकारी। सूचना के अधिकार में जानकारी देने के मामले में ये शूकरों की फौज चूंकि भ्रष्टाचार की गंदगी में लोट लगाने के आदि है, इसलिए कोई जानकारी देने की तो दूर आवेदन को ही रद्दी की टोकरी में डाल देता है, क्योंकि इनका आका सूचना आयोग को ही महीना भेज देता है। स्वाभाविक है कि प्रधान कार्यालय में बैठे चाहे वह यांत्रिकीय विभाग का मुख्य अभियंता सक्सेना हो, चूंकि पूरे म.प्र. के आठो कार्यपालन अभियंताओं से महीना वसूली करता है इसलिए ये हरामखोर भी जरूरत से ज्यादा स्याना बनकर, अपने कार्य पालन अभियंताओं को बचाने में लगा रहता है, जबकि ये हैण्डे पंपों की 50 से ज्यादा मशीनों में हर वर्ष की मरम्मत और रखरखाव का ही करोड़ों में कमीशन बटोर लेता है। दूसरा फिर हैण्डपंपों और पाइपों की भी अनाप-शनाप खरीदी में भी 5% कमीशन में भी इन आठों कार्यपालन यंत्रियों से अपने वारे-न्यारे कर लेता है। स्वाभाविक है कि कमीशन की वसूली के चलते इसने जुलाई और अक्टूबर में भेजे गये पत्रों की न तो जानकारी दी और न ही उन्हें आठों संभागों में भेजा। इसके विपरीत भोपाल के पत्रकारों से दबाव अवश्य डलवाया कि ज्यादा पत्र न भेजो ओं जानकारी के लिए परेशान न करो, अर्थात ये सारे कुकर्म करें और जानकारी मांगों तो भोपाल के पत्रकारों को टुकड़े डालकर ये दबाव भी डलवायेंगे।

जनता को पानी पिलाने की व्यवस्था करने में मुख्यमंत्री कार्यालय से रिश्वत का पानी खींचने की प्रक्रिया शुरू होकर अंतिम छोर पर बैठा सुपरवाइजर और हैण्डपंप मेकेनिक तक जनता की जेब से वसूले गये धन के आवंटन को कैसे पीते है। वह लोक स्वार्थ यांत्रिकीय विभाग की कार्य प्रणाली से समझा जा सकता है।

म.प्र. प्रदूषण संरक्षण मंडल प्रदूषण कानूनों की आड़ में दोनों हाथों से 10 करोड़ रुपए साल की वसूली

19 वर्ष से कुंडली मारे बैठा और वसूली कर रहा मिश्रा

पूरे विश्व में बढ़ते प्रदूषण से बढ़ते तापमान, बिगड़ते मौसम चक्र से न केवल पर्यावरणविद् वरन सरकारें और जनता के साथ ही, सभी पशु-पक्षी और मूक वनस्पति जगत भी परेशान है। इसके विपरीत कम से कम म.प्र. सरकार का मुख्यमंत्री पाखंडी शिवराज, आवास और पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया, पूरा म.प्र. प्रदूषण फैलाओ मंडल इसका अध्यक्ष एन.पी. शुक्ला आयातित भुखेरा सचिव आर.के. जैन, प्रदेश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों क्षेत्रीय अधिकारी, अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स और कर्मचारियों को बस वसूली मिलती रहे, पर्यावरण जाये भाड़ में। वसूली चुकाकर, कानूनी कागजी खानापूर्ति खुलकर प्रदूषण फैलाओ पैसे की आड़ में, का खेल चहुं ओर खुलकर चल रहा है। इसका अंदाजा पाठक इस बात से ही लगा सकते हैं कि म.प्र. के प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अकेले इंदौर ऑफिस में बैठा क्षेत्रीय अधिकारी अच्युत आनंद मिश्रा जो 1991 में यहां सहायक इंजीनियर बनकर आया था, यहीं पर पदोन्नति लेकर क्षेत्रीय अधिकारी बनकर जमा हुआ है। समय माया व अन्य समाचार पत्रों ने जब सन् 2000 से लगातार इस हरामखोर के वसूली और भ्रष्टाचार के साथ लंबे समय से कुंडली मारे रहने के समाचार प्रकाशित किये तो मात्र डेढ़ वर्ष से भी कम समय के लिए 2004-05 में भोपाल गया ओर वापिस लौटकर आकर कुंडली मारकर जमकर बैठ गया। इसके भ्रष्टाचार और वसूली के चलते पूरा सांवेर रोड, पोलोग्राउंड, लक्ष्मी नगर, नेमावर रोड, मांगलिया आदि की हजारों फैक्ट्रीयां जिसमें दवाईयां, प्लास्टिक, रसायन, बियर फैक्ट्री, तेल, टेक्सटाइल, रंगाई आदि की फैक्ट्रीयों से निकलने वाले प्रदूषित जल से अधिकांश भूजल प्रदूषित और बदबूदार होकर एक तरफ वनस्पतियों को बर्बाद कर रहा है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय लोगों में पेट की बीमारियों, चर्म रोगों की बढ़ोत्तरी कर रहा है। साथ ही दुधारू पशुओं जो इस पानी को गाहे-बगाहे पी लेते हैं। अकाल मृत्यु का कारण बन रहा है। अकेले पोलोग्राउंड और सांवेर रोड की फैक्ट्रीयों का भारी रसायन युक्त जल एमआर-10 से बहकर मांगिया, जाखिया गांवों से बहकर खान नदी में मिलता है,जिससे पूरी खान नदी का जल भी प्रदूषण युक्त हो जाता है। अकेले पोलोग्राउंड में ही ....प्लेथिको, जैसी बड़ी दवा फैक्ट्रीयां टनों से प्रदूषण युक्त जल को बिना उपचार किये नाले में बहा देती हैं। वैसे भी मंझले दर्जे के इन रसायन और दवा उद्योगों को शीघ्र ही शहर से बाहर कियाजाना चाहिये, जिसकी मांग समय माया लगातार 10 वर्षों से कर रहा है, क्योंकि इनके चारो तरफ घनी बस्तियां बस चुकी हैं और इप्का के रसायनों की बदबू वर्षों से चारों तरफ फैल कर लोगों का जीना मुश्किल किये हुए है। पर इस भुखेरे गिद्ध मिश्रा के कारण उनका विस्थापन संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही 400 के लगभग दाल मिलों से भी वायु प्रदूषण फैलता है। इनसे भी क्षेत्रीय अधिकारी मिश्रा लगभग रुपए 50 लाख प्रतिवर्ष वसूल कर कोई कार्यवाही नहीं करता है। इसी प्रकार 400 से ज्यादा नर्सिंगहोम्स ओर हॉस्पिटल्स से भी रुपए 50 लाख से ज्यादा की वसूली करता है और दिखावे के लिए इसने इनका नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल का एक संगठन बनाकर एक-दो वेन चला रखी हैं; जो इनका कचरा इकट्ठा कर जलाने का नाटक करती हैं, जबकि इनका भस्मक कहां है इसका किसी को पता नहीं है। जबकि एमवाय हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, बीमा अस्पताल के जो भस्मक लगे थे वर्षों से बंद पड़े हैं। पर विरुद्ध बंदे ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की।

यह बंदा तो फैक्ट्रीयों के लायसेंस के नवीनीकरण में ही रुपए 50 लाख से ज्यादा वसूलता है। नये लायसेंस में रुपए 15000 से लेकर उद्योग के आकार के अनुसार रुपए 2 से 5 लाख की वसूली कर आंख मींचकर लायसेंस दिये जाते हैं।

पूरे शहर में 5000 से ज्यादा उद्योग, वर्कशॉप, आइल, फ्लोर, दाल मिलें, नर्सिंगहोम्स, हॉस्पिटल्स आदि से मात्र इस क्षे.अ. को रुपए 5 करोड़ से ज्यादा की वार्षिक आय होती है। अवैध वसूली से इसलिए बंदा कोई कितना भी प्रदूषण फैलाए इसकी औकात से बाहर होता है उसके विरुद्ध कार्यवाही करना, जहां तक म.प्र. प्रदूषण फैलाओ मंडल के अध्यक्ष एन.पी. शुक्ला का सवाल है, बेचारा रु. 10-20 लाख खाकर ये भी चुप रहता है। वही हाल इस विभाग के मंत्री का है रुपए 25-50 लाख पाकर मंत्री जयंत मलैया भी चुप रहते हैं। जहां तक इस क्षेत्रीय अधिकारी मिश्रा की शिकायतों का सवाल है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तक इसकी शिकायतें सैकड़ों में पहुंचती हैं, परन्तु बंदा रुपए 2 करोड़ प्रतिवर्ष बांटकर कुंडली मारे मौज मस्ती और अय्याशी में व्यस्त रहता है। शाम के 7 बजे के बाद, आप इसे शहर के बड़े नामी-गिरामी होटलों में देख सकते हैं। फिर इसकी अय्याशी के किस्से तो कई साप्ताहिकों ने वर्षों पूर्व भी छापे हैं। अधिकांश स्टाफ यहां पर अवैध वसूली के दम पर करोड़पति है और नियुक्ति से वर्तमान तक 20-20 वर्ष पूरे करने के बाद भी यहां वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, लेखाधिकारी से लेकर बाबू तक सब यहीं पर डटे हैं; तो मात्र लूटो और लुटाओ के दम पर। ज्यादा से ज्यादा स्थानांतरण के नाम पर धार क्षेत्रीय कार्यालय जिसका ऊपर ही कार्यालय है स्थानान्तरण कर औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती हैं। धार के क्षेत्रीय अधिकारी त्रिवेदी को भी यहां पदस्थ हुये 4 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। वे ही हैं क्षेत्रीय अधिकारी त्रिवेदी जो अपने खानदान में पुलिस अधिकारियों के होने का रुतबा झाड़ता है, जिसने .....से लेन-देन कर यूनियन कार्बाइड के 2200 टन .....अन्य जहरीले पदार्थों को लाकर दफनाने का षड्यंत्र रचा था; जबकि रामकी इंवायरो हैदराद की भारी भ्रष्ट कं. है। जिस तरह से 60 एकड़ के प्लाट का डिजाइन दिखाया व बनाया गया था, जिसकी लागत रुपए 25 करोड़ थी जिसमें रुपए 8 करोड़ की सब्सिडी थी, म.प्र. ओ.के. वि.नि. इंदौर ने मात्र 20 एकड़ का ही प्लाट दिया। इस रामकी इंवायरो ने इसका भरपूर फायदा उठाया रुपए 8 करोड़ का अनुदान हजम कर रुपए 2 करोडत्र से भी कम लगाये ऊंची बाउंड्री वाल बनाई अंदर क्या किया किसी को नहीं मालूम। जहां पर प्लाट दिया उस पहाड़ी से

बरसात का पानी बहकर चंबल में मिलता है। इस क्षेत्रीय अधिकारी त्रिवेदी के संरक्षण में रामकी इंवायरो खुलकर पर्यावरण और प्रदूषित पदार्थों को नष्ट करने के नाम पर वसूली करता है जो प्रतिवर्ष करोड़ों में होती है। भस्मक भी प्रोजेक्ट में दिखाये अनुसार नहीं है।

इंदौर से आनेवाला आवास व पर्यावरण के मंत्री, सचिव, प्रदूषण फैलाओ का अध्यक्ष, आयातित सचिव जो तकनीकी शिक्षा से केवल लूट और वसूली के लिए आया आर.के. जैन उनके रिश्तेदारों आदि इंदौर में अगवानी से लेकर खरीदी तक के आने जाने के सारे खर्चों को क्षेत्रीय अधिकारी मिश्रा, त्रिवेदी ही उठाते हैं तो कौन मूर्ख हुआ है; जो इन दोनों ओर यहां के वर्षों से जमे स्टाफ को हटायेगा। सूचना के अधिकार में पत्र देने पर इस क्षेत्रीय अधिकारी मिश्रा व त्रिवेदी का स्टाफ ऐसे भड़कता है, जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया हो, एक पत्र भी अजमेरा ने क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर व धार को भोपाल के माध्यम से पहुंचाया तो धार ने तो जवाब ही नहीं दिया, इंदौर कार्यालय से जवाब आया भी तो समय के बाद और जब पैसा जमा करने के लिये कर्मचारी को भेजा तो इंदौर कार्यालय के भ्रष्ट स्टाफ में कर्मचारी तो गुर्राने लगे परन्तु वहां की बत्तमीज महिलाएं उसको मारने भी दौड़ी, और उससे पेपर छीनकर फाड़कर फेंक दिये जब पाठक अंदाजा लगा सकते है। कि कितने बत्तमीज हैं इंदौर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी। इनकी शिकायत भोपाल कार्यालय को, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को की गई; पर सब इस क्षे.अ. से हिस्सा बटोरते हैं। कोई ने कुछ भी नहीं किया। ये है मुख्यमंत्री पाखंडी शिव के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का छोटा सा एक मात्र दृश्य। ऐसा हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के चलते खुले में चल रहा है। मुख्यालय को अपील भी की गई परन्तु खुले में पक्ष तो टुकड़ेखोर टुकड़े डालने वालों का ही लेंगे। यही हाल उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, सतना, रीवा आदि सभी का है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी 2000 को एक फैसले में कहा था भ्रष्टाचार के चलते सारे देश के भ्रष्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को तत्काल बंद कर देना चाहिए।

सड़कों पर गड्ढों, कीचड़ और खुदाई से जन जीवन दूभर

अधिकारी, नेता मस्त, जनता सड़कों से त्रस्त

सभी हरामखेरों को कमीशन चाहिये, बीआरटीएस, सेतु निर्माण आई.डी.ए., नगर निगम, लोक निर्माण, कल की कल देखेंगे

इंदौर। माल-बांट की राजधानी में सभी केवल माल बंटोरने की नियत आये हरामखोर अधिकारी और नेता जनता को कैसे रुलाते हैं, यह जनता पिछले 5 से ज्यादा वर्षों से देख और भोग रही है। चारो तरफ की सड़कें खुदी पड़ी है। बड़ी खाइयां खोद दी गई हैं। पिछले 4 माह से एलआईजी तिराहे से माहिदपुर वाला फर्नीचर के तिराहे तक सड़क खोद दी गई है और हरामखोर ठेकेदार चींटी चाल से काम कर रहा है। वही हाल पलासिया चौराहे से गीता भवन चौराहे तक का भी है, जबकि ये कितनी महत्वपूर्ण सड़क है। महापौर मोघे, निगमायुक्त, कलेक्टर ने इस सड़क पर काम शुरू करवाने से पहले कोई भी विकल्प तैयार नहीं किया, न सड़क पर कहीं बोर्ड लगाया कि यह सड़क बंद होने पर इस वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। अटल गेट से जंजीर वाले चौराहे तक जोड़ने वाले मार्ग की लक्ष्मी मेमोरियल जो कि अवैध रूप से नाले की जमीन पर बना है, के निकट की पुलिया को 5'-5' दोनों तरफ आसानी से चौड़ा किया जा सकता था, चौड़ा कर दिया जाता तो वहां पर दिन 10-20 बार लगने वाले जाम से बचा जा सकता था; पर किसी भी हरामखोर नेता या प्रतिनिधि को इससे कदापि मतलब नहीं है। सबको मोटे कमीशन से मतलब है। यही हाल मल्हारगंज चौराहे से मालगंज चौराहे का भी है, जो राज मोहल्ले से जुड़ताहै। यहां पर भी भारी कीचड़, गड्ढे, और खुदाई से वहां रहने वालों और उस पर चलने वालों का जीना दूभर हो गया है, न जाने किस क्षण मौत किसको गले लगा लेगी; किसी को नहीं मालूम। हर रोज अकेले इंदौर शहर की ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों पर दिये गये जालसाल ठेकेदारों के काम के चलते दुर्घटनाओं में 24 घंटों में एक दो व्यक्ति दुर्घटना और मौत के शिकार हो रहे हैं, दो पहिया वाहन गड्ढों, कीचड़ और खुदाई के चलते रात के अंधेरों में कैसे गिरते-पड़ते निकलते हैं ये वही जानते हैं। ऐसी पूरे इंदौर में दो पांच दस नहीं वरन सैकड़ों महत्वपूर्ण सड़कें हैं। फिर सड़कें भले ही सीमेंट कांक्रीट की बना दी गई हों कहीं पर भी बरसात का पानी,घरों, दुकानों की नालियों का पानी निकालने की बिना नियोजन कार्य होने के कारण व्यवस्था ही नहीं की गई; सिटी इंजीनियर, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग, इं.नि.प्रा. लोक निर्माण विभाग, कलेक्टर, नगर निगम में बैठे किसी अधिकारी को यह नहीं समझ में आया जबकि इन सभी विभागों में जनधन से करोड़ों रुपए का वेतन हर माह बंटता है कि सड़कें बनाने से पूर्व नालियों और उसके जल निकासी की उचित व्यवस्था पूर्व में ही की जाए, जो कि नियमानुसार हर शहरीय ग्रामीण, दो चार, छह लेन में की जानी चाहिए थी। परन्तु गिद्ध इंजीनियर जो भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग के डिग्री डिप्लोमाधारी हैं ने जानबूझकर नहीं की ताकि हर बार पानी भरने से सड़क खराब होगी और फिर बनवायेंगे हर बार ये बिलों में से 35 से 50% तक कमीशन डकारने का इंजीनियर्स से लेकर पार्षदों, महापौर निगमायुक्त, बिल पास करने वाले बाबू से लेकर लेखाकार हर किसी को उसके मुंह के आकार का भ्रष्टाचार की गंदगी का टुकड़ा श्वानों की भांति लपकने को मिलेगा। शहरीय सड़कों का काम क्यों 24 घंटों नहीं

चलता; फ्लड लाइट लगाकर सभी निश्चित अवधि के काम किये ही जाते हैं। एबी रोड का 1100 मीटर का टुकड़ा 3 माह से बना रहे हैं पर किसी भी बत्तमीज अधिकारी इंजीनियर, पार्षद, महापौर निगमायुक्त को शर्त की तो दूर देखते तक नहीं, कि कार्य क्यों कछुआ गति से चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में ही सैकड़ों की जानें जा चुकी हैं; हजारों घायल हो चुके हैं।

राजेन्द्र नगर बाणगंगा आदि जितने भी पुल बना रही म.प्र. लोक निर्माण विभाग के सबसे भ्रष्ट, महा निकम्मे भुखेरे श्वानों की फौज सेतु संभागों, में पाई जाती है। जो मात्र महंगाई दर वृद्धि से कमीशन खाने के लिये, किसी भी पुलों रेलवे ओवर ब्रिजों, का कभी भी कोई भी कार्य म.प्र. के आठों संभागों में, समय पर पूरा इसलिए नहीं किया ताकि जितना लंबा खींचेंगे उतनी ही महंगाई की दर बढ़ने पर इन गिद्धों को ठेकेदारों के साथ मिलकर कमीशन डकारने, शासन को चूना लगाने का मौका मिलेगा। फिर काम न करने वालों को बहानों की कोई कमी नहीं होती; जहां तक बाणगंगा ओवल ब्रिज का सवाल है, तो ....जिसका एमआर-10 की क्रासिंग पर टोल ब्रिज है, इस सेतु संभाग के इंजीनियर को ये भी पैसा दे रहा है ताकि जितना काम लटकेगा उसे उतना ही ज्यादा टोल ब्रिज पर ज्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा ये तो हुआ लोक निर्माण विभाग, नगर निगम आईडीए, की पलासिया चौराहे पर रोड सेपेरेटैर बनाने की बकवास ओर लूटने खाने की योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। वहां केवल चौड़ाई बढ़ा देने से भी पूरा यातायात का दबाव कम किया जा सकता है; जानबूझकर पलासिया थाने के पास वाला पुल दोनों तरफ 10'-10' चौड़ा नहीं किया जा रहा ताकि रुपए 50 करोड़ की लागत से ज्यादा के ग्रेड सेपेरेटर में मोटा पैसा डकारने और जनता को 2-5 वर्ष तक परेशान करने का मौका मिल सके।

पूर्व जिलाधीश विवेक अग्रवाल ने जिस तरह से पूर्व जालसाजी के तहत जेएनआरयूएम के तहत बसों के लिये पैसा केंद्र से लिया वह पैसा कहां डकारा गया अरबों रुपए, जबकि सारी बसें ठेकेदारों की हैं। फिर बसों के चलाने के लिये बस रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़कों के विकास के लिए रुपए 868 करोड़ स्वीकृत करवा लिये जबकि पूरे शहर में जवाहर मार्ग, एमजी रोड को पिछले 4 वर्ष से कितना चौड़ा किया गया था। भविष्य में दोनों तरफ की साइट को कैसे हटायेंगे, कितना मुआवजा देकर कहां विस्थापित करेंगे। कोई नियोजन न तो तय था और न अभी है। न अगले 25 वर्षों में ऐसा कुछ कर सकेंगे।

इंजीनियरिंग और शहरीय विकास में सिविल अभियंताओं के साथ उच्च सिविल इंजीनियरिंग की सलाहकार संस्थाओं के साथ और उनकी सलाह पर काम किया जाना चाहिये इंडियन एब्यूसिंग सर्विसेज के अधिकारियों का जहां तक सवाल है; तो ये पूरे देश में भ्रष्टाचार से धन बंटोरने के अतिरिक्त इन हरामखोरों ने अपने स्वार्थों के चलते डॉक्टरों, इंजीनियरों और अपने मातहतों को गाली देने के अतिरिक्त ये न तो किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं; न ही बहुत अध्ययनशील, बस इन्हें देश के खुदा होने के झूठे दंभ के अतिरिक्त इनके पास बहुत कुछ विशेष ज्ञान नहीं होता, फिर हर जगह टांग अड़ाना, उलटी सीधी बेसिर-पैर की सलाह देना, अपने मातहतों को हड़काना अपने मंत्री-संत्रियों को मूर्ख बनाना इन्हें खूब आता है। ये जो कहें तो कानून है; इसके लिये उन्हें कुछ भी करना पड़े; नेता, मंत्री शतरंग की बिसात के मोहरे, जैसा तो नचायेंगे तो नाचेंगे उपरोक्त सत्यता बीआरटीएस के रुपए 868 करोड़ की है; जिसके अंतर्गत मात्र राजेन्द्र नगर से मांगलिया तक का एबी रोड का हिस्सा ही था, जिसमें ही करीब रिंग रोड चौराहे तक पहले ही बन चुका था, मांगलिया गांव से रिंग रोड तक लोक निर्माण विभाग के पास है। महानगर की लगभग इस 15 कि.मी. लंबी सड़क पर चलने वाले और रहने वाले पिछले 5 वर्षों से भोग रहे हैं।

यहां हवा में महल बनाने की कोरी काल्पनिक योजना दीजिये, सारे भाग्य विधाता आई.ए.एस. को समझा दीजिये कि 110% में रुपए 50 करोड़ आपका कमीशन है; वो उस योजना को स्वीकृत कराने; कागजों में काल्पनिक आंकड़े भरने, सपनों का संसार सजाने; 100-200 नहीं वरन 10-20 हजार को मरवाने से गुरेज नहीं करेगा। फिर अभी तक बीआरटीएस में मात्र 347 लोग ही मौत का शिकार हुए हैं। फिर कांक्रीट की सड़कों में नया डामर की सड़कों की तरह तन्मयता पाई जाती है; दूसरा जो भी दो पहिया वाहन चालक सिर के बल सड़क से टकरायेगा सीधा मौत के मुंह में जायेगा; तीसरा बरसाती पानी के लिये इन सड़कों पर सही निकासी न होने और मिट्टी बिखरने या मिलने से दो पहिया वाहनों के पहिये फिसलने से सीधी मौत या गंभीर घायल ही हो रहे हैं लोग, चौथा 100' से ज्यादा कांक्रीट की गुणवत्ता देखिये कि बनते-बनते ही चटकने और उखड़ना शुरू हो गई, पांचवा समतल नहीं है सड़क दूर से देखने पर अलग ही ऊपर नीची दिखती है। कुल मिलाकर सारी कहानी हरामखोरी और कमीशनखोरी की है। फिर कांक्रीट की सड़कों पर हर सौ मीटर पर सड़क के नीचे 1' से 2' व्यास के पाइप क्यों नहीं डाले जा रहे ताकि भविष्य में किसी पाइप लाइन, गैस लाइन, केवल या क्रॉस नाली बनाने की जरूरत पड़े तो पूरी सड़क न खोदनी पड़े हर 20'-30' पर सड़क के बरसाती पानी को निकालने के लिये भी सड़कों के नीचे से पानी बह सके, ये है इंजीनियरों के कमीशनखोरी के चलते दिमागी दिवालियेपन का सबूत उस पर इंजीनियरिंग सलाहकार फर्मों को करोड़ों का भुगतान आई.डी.ए., नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को यह सब नहीं दिख रहा, चूंकि संबंधित सभी का कमीशन है इसलिये कोई कुछ भी नहीं बोलेगा जनता को वर्तमान में और भविष्य में परेशानियां हो रही हैं और होंगी कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं, सभी आंख मींचकर कमीशन का दूध पीने में जुटे हैं।

भाजपा सरकार -पूंजीपतियो ओर कॉलोनाइजरो की रखैल

भूमाफिया के इशारे पर शिव का भू तांडव

वन, सरकारी, नजूल, कृषि भूमि पर कॉलोनाइजरो और खदान माफियाओं, उद्योगपतियो को औने-पौने

भोपाल। भाजपा की सरकार प्रदेश की वन, सरकारी, नजूल और कृषि भूमि को बड़े राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय भूमाफिया, कॉलोनाइजर्स 8माल माफिया उद्योगपतियों को अपना मोटा कमीशन डकार कर चारों ओर मुक्त हस्त से बांटी जा रही है। इसके लिये जो कमी इंवेस्टर्स मीट का नाअक इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में करती है,जब ज्यादा हल्ला मचता है इसलिए पाखंडी मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रेस और मीडिया से दूर आध्यात्मिक रति और पर्यटकों की नगरी खजुराहो में इस बार इंवेस्टर्स मीट को किया गया, जहां इस इंवेस्टर्स मीट की आड़ में, जनता के धन से प्रत्यक्ष में सुरा और परोक्ष में घ्झर के बाहर घर जैसी सुविधायें उपलबध करवा कर रुपए 2 लाख करोड़ से ज्यादा विनियोजन का पाखंड किया गया; जबकि रिलायंस, टाटा जैसे अधिकांश जालसाज उद्योग लगाने के पुराने दावों को ही दोहरा दिया ये वो अच्छी तरह जानते हैं कि इंदौर में ही उद्योगों के नाम जमीनें किसानों से कृषि भूमि अधिग्रहीत कर किस पर भूमाफियाओं को शासन के खर्चे पर औने-पौने बांटी जा रही है। अकेले इंदौर में ही अंसल, डीएलएफ, सहारा सिल्वर स्प्रिंग, रिलायंस, पार्श्वनाथ बिल्डर्स, जैसे लगभग 200 भूमाफियाओं ने नजूल की, कृषि भूमि, नदी-नालों, यहां तक की तालाबों के केचमेंट क्षेत्रों की, सरकारी, चरनोई की, ग्राम पंचायतों की, कृषि की भूमि पर लगभग 200 से ज्यादा कॉलोनी रिंग रोड पर, बाईपास पर पश्चिमी रिंग रोड पर खड़ी कर दी है; इसमें सरकारी धन का छोटा सा उदाहरण ये है कि जानबूझकर, एडीबी के ऋण से, जो नर्मदा का तृतीय चरण से शहर वालों को पानी मिला, नहीं मिला परन्तु इन कॉलोनियों को जो कि पूर्णतः अवैध है; को अवश्य यहां नगर निगम के आयुक्त, महापौर जिलाधीश को, संभागायुक्त को और लो.स्वा.यां. विभाग अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्रियों को करोड़ों रुपए बांटकर पानी की आपूर्ति निश्चित कर दी गई, जबकि ऊर्जा नगर निगम के सिर है, जो कि पानी की कीमतें रुपए 60 से बढ़ाकर 200 कर दी गई, जबकि आधे इंच के नल कनेक्शन में महीने भर में मात्र साढ़े सात घंटे ही दिया जाता है; वह भ बिना प्रेशर का; दो दिन में एक बार मात्र आधा घंटा, पूरे शहर को पिछले 4 वर्ष से बड़े-बड़े लटके-झटके दिये जा रहे थे, 90 एमएलडी पानी आया कहां चला गया मालूम पड़ा कि सारा पानी भूमाफियाओं की नई अवैध कॉलोनियों में बंट रहा है। यही हाल भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में भी हो रहा है।

भाजपा की पूरी सरकार और उसके मंत्री कैसे भूमाफियाओं के इशारे पर नाचकर न केवल पूरे प्रशासनिक तंत्र को गुलाम बनाकर जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, जिलाधीशों से लेकर सरपंचों तक को टुकड़े डालकर वहां रिक्त पड़ी कैसी भी भूमि हो, आसपास की कृषि भूमियों को खरीदने के बयाने देकर, फंसाकर पहले कृषि भूमि और पहाड़ों, नदी-नालों, चरनोई, वन भूमियों पर भी अपनी बाउंड्री वाल बनाकर कॉलोनी खड़ी कर देते हैं। फिर सबको यथा योग्य मोटी रिश्वत का टुकड़ा डालकर उसे वैध बनाने की चाले चलते हैं। पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से लेरक पक्ष-विपक्ष के विधायक इनके विरुद्ध मुंह नहीं खोलता है। इसके लिए बाकायदा भाजपा की पूरी सरकार हर चौथी-पांचवी मीटिंग में उसे वैध बनाने के लिए कानूनों में फेरबदल करने, कानून बनाने ऐसी भूमियों जो सरकारी है, नजूल की है; किसी नदी-नाले के आसपास की तालाबों या बड़े जलस्त्रोतों के केचमेंट क्षेत्र की है; या वन भूमियों तक पर कॉलोनी, शॉपिंग माल, उद्योग, व्यावसायिक पार्क, होटल, पर्यटकों की ऐशगाह, आरामगाह बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ये सारी भूमियां ये भाजपाई केबिनेट के डकैत अपना मोटा कमीशन डकार कर ही बांट रहे हैं। बेशक भाजपा यह जानती है और मानकर चल रही है कि अब इनकी सरकार सत्ता में नहीं आयेगी इसलिये प्रदेश की सत्ता में रहकर, सारा प्रदेश, देश, विदेश और प्रदेश के पूंजीपतियों को जैसे वो चाहें नीलाम कर जैसे लूट सके तो लूट, अंतकाल पछतायेगा जब सत्ता जायेगी छूट की तर्ज पर, निगमों, विभागों, मंडलों, जिसमें सड़क परिवहन निगम की सारी संपत्तियों यथा डिपो की जमीनें, बस स्टैण्ड, कार्यालय की जमीनों को औने-पौने बिक्री, म.प्र. विद्युत मंडल की संपत्तियों, पावर हाउसों, खंभों से लेकर हर वस्तु उद्योगपतियों के हवाले कर पैसा बंटोरना चाहती है इसलिये 31/03/2011 से मंडल बंद; पहले उसकी कंपनियों में बैठे धूर्त गिद्ध एम.डी.आई. ए.एस. अरबों रुपए की बंदर बांट कर डकार लेते हैं और घाटे दिखाकर पूंजीपतियों को बेचने पर तुले हैं। शक्ल से भोले दिखने वाले शिव का राज उसके पीछे छिपे मक्कार और चालाक उस व्यक्ति से है; जो पुरानी विधान सभा के मिंटो हाल, उसके चारों तरफ की सरकारी 175 एकड़ जमीन को बेंचने या लीज पर देने का कारगुजारी से ही जानी जा सकती है। एक तरफ कृषि को लाभ का धंधा बनाने की बात करता है, तो दूसरी कृषि भूमि पर टाउनशिप निर्माण के लिये असीमित कृषि भूमि खरीदने के और इस जमीन को कृषि जोत, उच्चत्तम सीमा अधि. के प्रावधानों से मुक्त करने की चाले चलता है।

साप्ताहिक समय माया

पैसे के खेल में सारे कानून फैल

4 खाद्य निरीक्षक निलंबित, निर्दोष स्थानांतरित, असली डकैत पद पर

पैसे के दम पर नकली, असली हो जाता है दिनेश साहू पर रासुका क्यों नहीं लगी

इंदौर। इस व्यावसायिक राजधानी में कदम-कदम जालसाजों, मिलावटियों का तो बोलबाला है। यहां पर ऊपर से जो भी सरकारी अधिकारी निरीक्षक, कर्मचारी है वो भी महा जालसाज, मक्कार, रिश्वतखोर हो जाते हैं। उसमें चाहे फिर जिलाधीशों, संभागायुक्तों से लेकर एसएसपी, एसपी तक सभी शामिल हैं। इसका उदाहरण है एसएसपी माहेश्वरी, जिनको चोरी की गाड़ियों का शौक है, जिसे डीबी भास्कर ने 20/11/10 के मुख्यपृष्ठ पर छापा है।

जिस दिनेश साहू पर जिलाधीश राघवेन्द्र सिंग नकली घी काण्ड में रासुका लगाने का हल्ला मचा रहे थे, मीडिया में छपवा रहे थे, लेन-देन के चलते सारा मामला ठण्डा कर दिया गया है। उसकी चार फैक्ट्रीयों में से मात्र दो ही पकड़ी गई और दो अभी शान से चला रहा है। खाद्य निरीक्षकों में, वरिष्ठता का पैसे के दम पर दर्जा प्राप्त कर अभी भी उसके महीने के भुगतान कर्ताओं के पेरोल पर दर्ज हैं और दो फैक्ट्रीयों के पैसे वसूल रहा है।

खाद्य निगम सचिन लोंगरिया इससे रुपए 25000/- प्रति माह पूर्व से ही वसूल रहा था। इसलिए इस पर स्वयं कभी कार्यवाही नहीं करता था; अंतिम बार भी कार्यवाही में शैलेश गुप्ता, खाद्य निगम अमित वर्मा से कार्यवाही करवाई गई, जिससे ये साफ बच निकला और इस पर किसी ने संदेह नहीं किया; जबकि इस खाद्य निगम सचिव ने कार्यालय से बिना बताए गोल मारकर और भोपाल में रहकर सारी रिपोर्ट्स को रुपए 14 लाख लेकर बदलवाया। लोक विश्लेषक चतुर्भुज मीणा जो कि फर्जी प्रमाण पत्र पर उज्जैन नगर निगम में पदस्थ है, पैसे का लेन-देन कर एक सप्ताह प्रति माह में, म.प्र. खाद्य प्रयोगशाला भोपाल का कार्य भी देखता है और खुले में लेन-देन कर सारे नमूनों को जिसमें 1 ग्राम भी शुद्ध घी नहीं होता। दिनेश साहू के नमूनों की भी आरएम मूल्यांकन रद्द कर दिया। इस नमूने पर भी .....चतुर्भुज मीणा के ही हस्ताक्षर हैं। इन नमूनों को बदलावाने में भी रुपए 17 लाख का लेन-देन हुआ, जिसमें अकेले सचिव ने रुपए 3 लाख, खाद्य नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव रुपए 5 लाख, रुपए 3 लाख उपनियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव झूठी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए रुपए 2 लाख चतुर्भुज मीणा के भुगतान की खबरें हैं। जिलाधीश इंदौर और एसडीएम को भी क्षेत्रीय स्तर पर मोटे लेन-देन के बाद उस पर रासुका लगाने का मामला ठण्डा हो गया, जबकि कांग्रेस ने इसकी सदस्यता से इसे हटा लिया। वैसे भी भाजपा में ऐसे ही माफियाओं की जरूरत है, जो पार्टी को येन-केन काला पीला धन दे सकें और नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जनता को मिलावटी, नकली माल बेंचकर मोटा धन कमा सकें। उनके मंत्री-संत्री भी ऐसे ही लोगों को पालते और संरक्षण देते हैं। इसी प्रकार सुभाष खेड़कर से खाद्य निगम सचिन लोंगरिया ने हींग पकड़ी थी उसे भी जब्त नहीं किया गया और रुपए 1 लाख का लेन-देन कर छोड़ दिया गया। ऐसा ही एक प्रकरण बुलाग इंटरप्राइजेस 28 रियल स्टेट कनाड़िया रोड इंदौर का है, जहां एक बूंद घी, मक्खन,क्रीम या बटर आइल नहीं मिला, वहां केवल वनस्पति घी, सोयाबीन तेल और नकली घी बनाने का इसेंस मिला। इस मनोज अग्रवाल की फैक्ट्री को जाली दस्तावेजों के आधार पर खाद्य निगम ने ही अरविंद तोमर के नाम से लायसेंस जारी किया था, चंकि वहां लोंगरिया की पहले से मासिक रुपए 25000/- बंदी बंधी हुई थी, उसने कभी एक भी नमूना नहीं लिया। इस फैक्ट्री से जो नमूने लिये गये और माल जब्त किया गया, जिससे पूरा इंदौर का खाद्य एवं औषधि विभाग भरा पड़ा है। आश्चर्य की बात यह है कि वह नमूना प्रयोगशाला में 17 आरएम के मूल्यांकन के साथ पास हो गया, यहां पर भी खाद्य निगम सचिव ने म.प्र. खाद्य प्रयोगशाला में भोपाल में रहकर सभी नमूनों को जांचने वाले रसायनज्ञों को पैसा खिलाकर आरएम मूल्य को 17 तक पहुंचा दिया, जबकि शुद्ध खालिस घी का मूल्यांकन भी 14.5 से ज्यादा नहीं जाता, इस खेल में भी रुपए 7 लाख के लेन-देन के समाचार हैं। यहां पर भी रुपए 4 लाख सीधे खाद्य नियंत्रक म.प्र. ने ही कारिस्तानी में लेकर सारा खेल करवाया। इस फैक्ट्री से सारा घी जब्त कर लिया गया, परन्तु मशीनों को छोड़ दिया गया, जबकि मनोज अग्रवाल जिसका सारा ..... विदिशा लिखा गया, जबकि वह पता ही गलत था, दूसरी ओर विनोद सिंघल द्वारा मशीनें बेंचने की तैयारी चल रही है। खाद्य प्रयोगशाला में बैठे रासायनज्ञों जिसमें मालादीन,राकेश जैन, विक्टर, गुप्ता केमिस्टों की सांठगांठ पर व उनकी तैयार रिपोर्ट का उज्जैन का ये लोक विश्लेषक धन लेकर आंख मींचकर अपने सात दिन के कार्यकाल में हस्ताक्षरित कर देता है। बेशक इस लोक विश्लेषक चतुर्भुज मीणा की नियुक्ति में संभवतः राज्य स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया के साथ्ज्ञ नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन उज्जैन की भूमिका महत्वपूर्ण है। वैसे भी मुख्यमंत्री शिव चौहान ढ़ींगे कितनी बड़ी हांके, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करें, पर मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मुख्य सचिव इकबाल सिंग, वैसे सचिव अनुराग जैन जैसे डकैतों और जालसाजों का ही बोलबाला है। खाद्य एवं औषधि नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी वहां डिप्टी कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव की पिछले तीन वर्ष से नियुक्ति कर विशुद्ध भ्रष्टाचार का तांडव ही करवाया जा रहा है। सही कारण है कि केन्द्र में जब राज्य के खाद्य नियंत्रक को जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को होना चाहिए, न होने पर विभाग के अन्य अधिकारी को केन्द्र सरकार के सम्मेलनों और सभाओं में भेजा जाता है। स्वाभाविक और स्पष्ट है कि भाजपा के इस भ्रष्ट प्रशासन को जनहित नहीं स्वहित देखना है। इन भुखेरे गिद्धों की बला से जनता कल की मरती आज मरे। मिलावटियों को सजा नहीं देना वरन उनकी मिलावट से कमाये धन को कानूनों की आड़ में अपने बैंक बैलेंस सजाने हैं।

इस सबका पाठक आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि इंदौर का यह भ्रष्ट डकैत, खाद्य निगम सचिव लोंगरिया ने अभी दीपावली पर भास्कर के पत्रकारों से लेकर जो भी भारी पड़ा उसे रुपए 10-20 हजार मुंह बंद करने के आसानी से बांटे जो कुल रुपए लाख-डेढ़ लाख से ज्यादा थे। यही कारण है कि भास्कर भी गाहे-बगाहे इसके छापों की कार्यवाही को प्रशंसा के अंदाज में छापता है। पैसा राज एक्सप्रेस, पत्रिका तक के पत्रकारों तक को बांटा गया, ताकि वो इसकी लूट-खसोट को न छापें। खाद्य अपमिश्रण विभाग के सभी नौ इंस्पेक्टर्स जिसमें उज्जैन का पूर्व डकैत अरविंद पथरोल भी अब इंदौर में ही है। सभी दोनों हाथ वसूली में जुटे हैं और बिल्ली की तरह रिश्वत का दूध पीते समय आंख मींचकर दोनों हाथों से जुट कर वसूली करते हैं। इंदौर की 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां 5000 लघु उत्पादक और पैकर्स, 10000 से ज्यादा छोटी दुकानों, 50 बड़ी होटलों, 500 से ज्यादा मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट, मिठाई नमकीन रुपए 10 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण विभाग के साथ नगर निगम के खाद्य निरीक्षकों को बांटते हैं।

अकेले खाद्य निगम सचिव लोंगरिया ने सांवेर में सरस नमक में पीली रेत की मात्रा बहुत ज्यादा थी माल जब्ती किया, फिर रुपए दो लाख लेकर मामला रफा-दफा कर दिया। इस नमक की आपूर्ति करने वाले कच्छ के व्यापारी से रुपए 1 लाख वसूला गया, बेशक ये खाद्य निगम लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, उपसंचालक स्वास्थ्य डॉ. शरद पंडित को भी रुपए लाख दो लाख महीना बांटते हैं। मोटे अनुमान के अनुसार अकेला खाद्य निगम रुपए 2 करोड़ की वूसली कर रुपए 1 करोड़ बांटता है। अब पाठक अंदाज लगा सकते हैं पूरे शहर में मिलावट का कारोबार कैसे फल-फूल रहा है। यही कारण है कि सूचना के अधिकार में न इनका क्षेत्रीय कार्यालय कभी ढंग से जानकारी देता है, न ही भोपाल कार्यालय। 30 नवंबर 2010 को घोषणा की गई चार खाद्य निरीक्षकों को निलंबन की। आदेश 15 दिसंबर 10 को फैक्स पर सीएमओ ऑफिस में आया। खाद्य निरीक्षक ठाकुर, पथरौल और गुप्ता को 15 दिसंबर को ही आदेश देकर स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु सचिन लोंगरिया जो इस षडयंत्र का सूत्रधार था उसने 20 दिसंबर तक आदेश ही नहीं लिया। और ऑफिस में बैठकर पुराने काम निपटाता रहा। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश खाद्य नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव ने रुपए दो लाख लेकर उससे वादा किया कि वे उसे वापस इंदौर में ही पदस्थ किया जाएगा।

मनरेगा ग्रामीण विकास के नाम लूट मची है लूट सके तो लूट

ग्रामीण यांत्रिकीय लूट और भ्रष्टाचार सेवा

जिलाधीश मु.का.अ. सब ही डकारते हैं, तो कैसे जांच करें का.अभि.ग्रा. यां. सेवा देवास की

पूरे देश में घोटाले हो रहे हैं, फिर मनरेगा तो लागू ही इसलिए किया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सत्ता की अंतिम इकाई ग्राम पंचायतों तक भ्रष्टाचार की गंगा समान रुप से बहे और ग्रामीण श्रमिक इतना नकारा निकम्मा बन जाये कि वो शासन की भीख पाकर अपने को धन्य समझ ले और सत्ताधीशों की वोटिंग मशीन बनकर जब भी वोट डालने को कहा जाये पंजे पर पंजा टिका दे, इसमें ये पंजे वाली सरकार न केवल सफल रही वरन भ्रष्टाचार के इस खेल में प्रधानमंत्री कार्यालय ग्रामीण मंत्रालय केन्द्रीय से लेकर राज्यों तक और राज्यों के गांवों तक बिल्ली की भांति आंख मींचकर धन पीटने में जुटे हुए हैं। इसकी छोटी सी बानगी देवास जिले की प्रस्तुत कर रहे हैं।

सूचना के अधिकार में ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग देवास सन् 08-09 और 09-10 की जनाकारियों के दस्तावेज प्राप्त किये गये, दस्तावेज देने में मई 10 के पत्र की जानकारी प्राप्त करते अक्टूबर 10 गुजार दिया गया, इस बीच मई 10 से अक्टूबर 10 यहां के धूर्त कार्यपालन यंत्री जेपी गौर, बागली एसडीओ अली और इनका महाधूर्त चेला म.प्र. जल संसाधन से आयातित बाबू राठौर जो अब अजगर की तरह इस योजना में अली और का.यं. गौर के साथ मिलकर 60% से ज्यादा फर्जी कार्यों को अंजाम देकर इस योजना में करोड़ों का पलीता लगाकर निगल रहा है। इसने भारी प्रयास किये खरीदने के, ताकि वो दस्तावेज हमें न देना पड़े, इसने भारी चमकाया कि मेरा एक बेटा मिलिट्री में हैं।

इस भ्रष्ट की काली कमाई का एक मकान 74 नं. स्कीम में है, अब पाठक स्वयं ही अंदाज लगा सकते हैं कि करोड़पतियों की इस कालोनी में सिंचाई विभाग के बाबू का बंगला कैसे बना होगा।

देवास में ग्रामीण रोजगार गारंटी का सबसे ज्यादा पैसा खर्च बागली विकासखण्ड में एसडीओ अली और इस बाबू राठौर द्वारा किया जाकर 40 से 60% पैसा सीधा डकारा जा रहा है। कार्य.यं. देवास द्वारा प्राप्त जानकारी में यह तथ्य स्पष्ट होता है। बेशक इस बंदरबांट में जिला पंचायत कार्यालय में भी जल संसाधन विभाग का आयातित ड्राफ्टमेन जो अब एसडीओ बनकर पिछले कई वर्षों से ग्रामीण विकास के नाम से प्राप्त धन में हर जगह वसूली में व्यस्त है, जबकि इसके रहते देवास में कई मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकर चले गये, वैसे भी जिला पंचायतों में पूरे देश और प्रदेश में अधिकांश मुख्य कार्यपालन अधिकारी सामान्य पंचायतों में 10 से 50 करोड़ रुपए और आदिवासी जिला पंचायतों जैसे धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग के डिंडोरी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल संभाग के उमरिया, डिंडोरी, शहडोल व अनूपपुर जैसे जिलों में बैठे जालसाज धूर्त और महाभ्रष्ट प्रति वर्ष रुपये 50 से रु. 200 करोड़ तक इस ग्रामीण और आदिवासी विकास के नाम पर डकार जाते हैं। सामान्य पंचायतों में ग्रामीण विकास की विभिन्न मदों रु. 1000 करोड़ से रु. 1500 करोड़ और आदिवासी जिलों में रु. 3000 करोड़ से रु. 5000 करोड़ आता है। अब यदि केवल 10% से 25% कमीशन और धन डकारने, जो कि बहुत साधारण सी बात है, इतना तो प्रादेशिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर न केवल प्रशासनिक वरन् अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के बारे में स्वीकारा जाता है।

जहां तक मनरेगा का सवाल है, तो यहां पर तो 60% मजदूरी जिसमें 10 से 20 % तक बंदरबांट होती है, झूठे, फर्जी यहां तक कि मृत लोगों और अव्यस्कों के नाम से जॉब कार्ड बनेहुए है और यह बागली का बाबु राठौर सरपंचों के माध्यम से उनका भी आधे आधे पर वसूली कर रहा है।

40% पैसा कुल लागत का सामग्री के नाम पर हजम किया जा रहा है। इसकी बानगी देखिए जन 1-10 से 31 मार्च 10 तक के तीन माह के जो फर्जी बिल भुगतान किये गये उनमें बागली तहसील के सहा. अभियंता अली ने गिट्टी मिट्टी और रेती के नाम अकेले घनश्याम नाम के आपूर्तिकर्ता के 150 व्हाउचरों का फर्जी भुगतान किया जिसमें 18 बिल × रु. 9897/- कुल रु, 1,78,146/- 12× 9899/- कुल रु. 1,18,788/-, 70 × 9884 = रु. 6,91,880/- 8×9570 = रु. 76560/-, 42 ×9697/- = 4,07,274 कुल 150 बिलों का रु. 14,72,658/-, दूसरे आपूर्तिकर्ता छोटू खां का भुगतान 25 × 9697/- = 2, 42, 425/-, 11 व्हाउचर × 9460 = 1,04,060/-, 7 × 9570/- = 66990/- कुल 43 व्हाउचर से रु. 4,13,475/- का भुगतान

आपूर्तिकर्ता राकेश कानूनगो 36×9697/- = 3,49,092/- 10×9884/- = 99840/-, 9×9884 = 88956/-, 4× 9360 = 37440/- कुल 59 व्हाउचर से रु. 5,75,338/-

अनवर खां - 16×9697 = 1,55,152/-, 14×9864/- = 1,38,376/- 6×9897 = 59382/-, कुल 36 से 5352,910/-

मंसूरी - 10×9570 = 95700, 13× 9922 = 28986/- कुल 23 व्हाउचरों का रु. 1,24,786/-

महेन्द्र का 32×9884 = 3,16,288/-

शफीक उज्मा खां का 34×9570 = 2,96,670/-

दिनेश बरपाल 12×9828 = 1,17,936/-

शर्मा - 8×9464 = 75712, 6×9984 = 59904/-

कुल 14 व्हाउचरों से रु. 1,35,616/- का भुगतान

भीमसिंग हीरालाल को 9×94641 = 85176 रु., 6000×5 = 30,000/- कुल रु. 1,15,1761रु. कुल 14 व्हाउचरों से

परसराम को 10×9570 = 95700/- का भुगतान किया गया।

पाठक, जांच एजेंसियां, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू अब आसानी से बंदरबांट का 50-50 के हिसाब से प्रकरण बनाकर भ्रष्टों को लपेट सकती है।

इसकी शिकायत इनके ही भ्रष्ट जिलाधीश सुश्री पुष्पलता सिंग और मुख्य कार्यपालन अधिकारी चौहान को की थी और स्पष्ट किया गया था कि इसकी जांच कर सूचित करें पर 2 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई जांच नहीं की गई। इसके दस्तावेजों के साथ लोकायुक्त को शिकायत भेजी जा रही है। जिसमें जिलाधीश सुश्री पुष्पलता सिंह और मु.का.अ. को भी भ्रष्टों को संरक्षण देने और हिस्सा डकारने में शामिल किया जायेगा, वैसे पाठकों को बता दें कि समय माया द्वारा लगातार देवास जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को छापने से कुपित होकर समय माया समाचार पत्र की डाक से भेजी जा रही प्रतियों जिलाधीश कार्यालय के आदेश पर डाकघर देवास बिना बांटे की सारी प्रतियों को लेने से इंकार लिखकर पिछले कई माहों से लौटा रहा है।

ये देवास ग्रामीण यांत्रिकीय की शिकायत तक एक छोटा सा हिस्सा है, जो ग्रामीण विकास के धन की लूट की स्वयं कहानी कह रहा है, चूंकि उपरोक्त सारे व्हाउचर रु, 10,000 रुपये से कम के हैं। जिन्हें एसडीओ ही पास कर भुगतान करवा देता है। इसके विपरीत रु. 10,000 से ज्यादा के व्हाउचरों में भुगतान की प्रक्रिया लंबी है। इसमें भी एक ही पार्टी से अलग-अलग नामों से बिलों का सीमेंट का लाखों में भगुतान किया गया जिसमें न तो टिन नं. था और नाम भी हाथ से ही लिखाहुआ था, ऐसे ढेरों मामले हैं। अब चूंकि सभी शामिल हैं, तो कौन किसकी जांच करेगा?

बिगड़ा यातायात संभलता नहीं और खीझ में

हेलमेट, सीटबेल्ट, के शिगूफे

प्रशासन स्वयं जिम्मेदार

इंदौर। फर्जी कं. में चलाई जा रही बड़ी-बड़ी बसें जहां से निकलती हैं, रोड जाम कर देती हैं। अब चूंकि उसमें जिला प्रशासन के सारे धूर्तों का हिस्सा है। कोई भी हरामखोर उसकी तरफ अंगुली नहीं उठाता। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी तो लिखते हैं हम सूचना अधिकार में नहीं आते। तो फिर आयुक्त जिलाधीश, महापौर उसके संचालक मंडल में कैसे हैं। सारा पैसा जवाहरलाल नेहरू शहरीय विकास का लगा है। दूसरी ओर सारी बसें ठेकेदारों की हैं। न कं. का प्रॉस्पेक्ट्स है। न शासन की मंजूरी इसके विपरीत बसें और टैक्सियां दौड़ रही हैं। पिछले 4 वर्षों से कं. की न बैलेंसशीट है, न लाभ-हानि खाता, अधिकारी क्या बंदरबांट कर रहे हैं अपने पिताजी की जागीर समझकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। सरकारी अधिकारी किसी भी दूसरे संस्थान में लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता और हमारे नगर के सारे प्रशासनिक अधिकारी उस कं. के लाभ में एक तरफ नोंच खसोट और बंदरबांट में जुटे हैं; तो दूसरी ओर कं. में लगे सारे अस्थायी कर्मचारियों को प्रशिक्षित श्रमिक का न केवल वेतन नहीं मिल रहा वरन् कं. में भविष्य निधि व अन्य श्रम कानूनों का लाभ भी नहीं मिल रहा, उस पर कोई भी पदाधिकारी न तो सूचना के अधिकार में जानकारी दे रहा है। जबकि 36'×9' की वो बसें पिछले 4 वर्षों में 1 सैकड़ा से ज्यादा को यमलोग और हजारों को अस्पताल में तो पहुंचा चुकी है। जहां उन बसों से टक्कर होने पर बीमा भी नहीं दिया गया। इस बात से पाठक अंदाज लगाये कि प्रशासन स्वयं कितना लापरवाह है। जब-जब यातायात बिगड़ने की बात उठती है सारे शूकरों की फौज हेलमेट और सीट बेल्ट के ऊपर खीझ उतारते हुए भौंकने लगती है। पुलिस के अधिकारी अपनी फौज का रोना तो रोते हैं। पर यह नहीं बताते कि उनके सिपाही मुस्तैदी से वसूली तो दो नं. और 1 नं. में पूरी करते हैं। पर यातायात सुधारने, निगरानी करने में उनकी मुस्तैदी सुस्ती में बदलकर चौराहों के कोने में खड़े होकर बतियाने में गुजरती है। निगमायुक्त और महापौर सड़कें खुदवाकर धीमी गति के समाचारों की तरह अत्यधिक धीरे काम करवाती है; ताकि अधिकतम बिलों के भुगतान में उनका भी मोटा अधिकतम कमीशन मिले और बंटें। इंडियन एक्यूसिंग सर्विस के कलेक्टर और कमिश्नर जिले और संभाग के राजाओं की भांति अपने दरबारियों से सुने राग अलापने और कमाई की व्यवस्था में लगे रहते हैं। उनकी बला से यातायात बिगड़े, जाम लगे, रोज 2-5 लोग दुर्घटनाओं में मारे 100-200 घायल हों, फिर पुलिस थानों की कमाई तो जितने अपराध होंगे उतनी ही कमाई होगी, यदि यातायात ही सुधर गया तो थाने, झक मारने के लिये बैठे हैं; क्या?

यही हाल भोपाल सिटी ट्रांसपोर्ट का है, वहीं जबलपुर, ग्वालियर का भी हैं पूरा का पूरा परिवहन विभाग नगरीय प्रशासन भ्रष्टों और जालसाजों का गिरोह है। उसे समस्यायें दूर नहीं करना वरन् समस्याओं के नाम कमाई करना और बड़ी कमाई के रास्तों की व्यवस्था करना है।

परिवहन विभाग कदम-कदम भ्रष्टाचार, जालसाजियां

दो पहिया को सीरीज पर हजारों चार पहिया पंजीकृत

फाइलें ही क्यों क्षे.प्ररिवहन कार्यालय को भी एजेंटों के घर से चलाओ

पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग ग्वालियर के मुख्यालय से लेकर संभाग और जिलास्तर तक हर कदम-कदम जालसाज अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या के 10 गुने परिवहन विभाग के जालसाज एजेंटों के सहारे हर दिन पूरे प्रदेश में रुपए 100 से 200 करोड़ की हेरा-फेरी करता है। जिन बसों के परमिट रुपए 1650 की फीस पर रूट परमिट जारी होते हैं उस पर लाखों की बोलियां और लेन-देन होते हैं। 50% यात्री बसें ट्रक न तो नियमित टैक्स भरती है। 100% यात्री बसें कानून के विरुद्ध चलाई जाती है। अकेले इंदौर में ही एल,एल,एन, की ए से जेड रोड तक की सीरीज दो पहिया वाहनों के लिए थी जिस पर हजारों कारें बसें और ट्रक तक चल रहे हैं। हजारों कारें सामान्य नं. की भी टैक्सी का कम किराया और रोड टैक्स भरकर चलाई जा रही हैं आखिर क्यों आरटीओ बनते हैं। डिप्टी कलेक्टर रेंक के अधिकारी केवल कमाई के लिये आते हैं। जैसे पूर्व का आरटीओ दिनेश जैन, वर्तमान में पदस्थ त्रिपाठी भी रुपए 5 करोड़ देकर इंदौर के ही आरटीओ बने, सीधा सा गणित है, कि रुपए 50 करोड़ की कमाई पर नजरे थी आरटीओ इंदौर में तो हर रोज कुछ न कुछ नया होता ही है। जालसाजियों के नाम, लोकायुक्त ने जो छापा मारा, मात्र चालक अनुज्ञप्ति के लिये जबकि वहां तो चारों तरफ स्टॉफ रूपी बड़े-बड़े मकड़ों के जालसाजियों के जाले हर रजिस्टर के हर पन्नों पर बिखरे पड़े हैं। चाहे वो ड्राठविंग लाइसेंस हो, पंजीयन हो, परमिट हों, किराया सूची हो टैक्सी कोटा हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र हो, शासकीय विभागों में भ्रष्ट शीर्ष होता है। परिवहन काय्रलय 5-5 वर्ष तक वहां अधीक्षक धूल धोये जैसे जमे रहते हैं और आरटीओ इंदौर के महत्वपूर्ण और मोटे लेन-देन के कार्य बाले-बाले घर से भी चलाया करते हैं। अगर आरटीओ से लेकर हर परिवहन के निरीक्षकों सहा. परि. अधिकारियों, बाबुओं से लेकर हर एजेंट के घर पर छापे मारे जाएं तो मालूम पड़ेगा बहुत सारी व्यवस्थाएं सामानान्तर घरों से भी चलाई जा रही हैं। उस पर वाहन पंजीयन की फाइलें मालिकों को देना तो सोने पर सुहागा हो जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन केवल वसूली

गैस, पेट्रोल, डीजल, पंपों पर मिलावट और कम नाप

जिला अधिकारियों, से निरीक्षकों तक को महीना दो और खुले में मिलावट करो, कम नापो,जनता को मारो, पीटो सब कुछ करो

कांग्रेस के आते ही देश में महंगाई का दुगुना होना, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, गैस की कीमतों में अनाप-शनाप वृद्धि उसकी कमाई और कमीशनखोरी का सबसे बड़ा स्त्रोत होता है।

पिछले 6 वर्षों में रुपए 35 का पेट्रोल बढ़कर रुपए 57 और रुपए 601 हो गया; कांग्रेस का शासन काल समाप्त होते-होते रुपए 75-80 तक पहुंचा देने की पूरी तैयारी है, जो सन् 2014 तक हो ही जायेगा। बाजार में जैसे-जैसे पेट्रोल, डीजल और एल.पी.जी., सीएनजी, की कीमतें बढ़ रही है; वैसे-वैसे पेट्रोल, डीजल में, सालवेंट, मिट्टे का तेल, आदि मिलाकर बेचा जा रहा है। दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और गैस को पूरे देश में प्रदेश में और इंदौर, उज्जैन, भोपाल के हर पेट्रोल पंप पर कम गैस, डीजल और पेट्रोल कम नापा जा रहा है। 10% से 50% तक पेट्रोल मार देना, जैसे एलपीजी, सीएनजी में वायुमंडल से वायु मिलाकर लीटर से नापी जा रही है। जो कि किलो से नापी जानी चाहिये, जबकि वसूली किले के मान से की जा रही है। इस लीटर से गैस नापने में उपभोक्ता का मात्र 500 से 600 ग्राम ही गैस मिल पा रही है।

इस बात को समय माया पिछले तीन चार वर्षों से बराबर प्रकाशित कर रहा है, परन्तु इंदौर के ही तीन-चार जिलाधीश बदल गये, परन्तु किसी ने भी उपभोक्ताओं की इस परेशानी लूट और पंपों की डकैती भ्रष्टाचार पर धयान नहीं दिया। सन् 2002-3 से सन् 2006 तक पंपों की इस लूट पर बराबर लिखते रहने का यह असर हुआ था कि कलेक्टर सुलेमान ने हर पेट्रोल पंप पर पारदर्शी पाइप लगाने को कहा था, परन्तु समय माया ने जनता की इस समस्या पर छापना या बंद किया कि सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

अकेले इंदौर में ही 150 से ज्यादा पेट्रोल डीजल और गैस पंपों पर सारे हरामखोर पेट्रोल पंप मालिक अपने हॉकरों और कर्मचारियों को जो वेतन कमीशन से मिलात है, वो तो देते ही नहीं, सारा हजमकर जाते हैं। दूसरी ओर शहरीय अधिकांश पेट्रोल पंपों से 4-6 प्वाइंटों पर उनके हाजिरी रजिस्टर में तो ज्यादा कर्मचारी दिखाकर कंपनी से तो वसूली करते हैं पर कर्मचारियों को रखते नहीं, बाकी बचे कर्मचारियों से रुपए 2/- प्रति लीटर की वसूली ऊपर से अलग से करते हैं; बदले में उलझाकर, सेटिंग फास्ट कर या झटके से स्पीड बढ़ाकर, इलेक्ट्रॉनिक पंप को गड़बड़ी कर न्यूनतम 10% से लेकर 50% तक पेट्रोल, डीजल और गैस कम नाप देते हैं। शाम को या हिसाब के समय कुल बेंचा गया, डीजल,पेट्रोल और गैस का कुल पैसा और बचे हुये चोरी के पैसे में से रुपए 1, 2 जैसे में रुपए 5 तक प्रति किलो के हिसाब से ऊपर मालिक को भुगतान कर बचे हुए पैसे को काम के हिसाब से आपस में बंदर बांट कर ली जाती है।

मिलावट जिसमें साल्वेंट, एचएसडी का पूरे देश में सबसे बड़ा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता रिलायंस पेट्रोलियम गुजरात है; जिसके कारखाने से अकेले इंदौर में ही 150 से ज्यादा टैंकर प्रति टैंकर 20,000 से 30,000 लीटर प्रति दिन इंदौर और आसपास के शहरों में मिलावट की जाती है। अधिकांश इंडियन आइल, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के इंदौर क्षेत्र के विपणन प्रबंधक भी इन सब पेट्रोल पंपों की कारगुजारियों में बराबरी के हिस्सेदार हैं। इन्हें भी मिलावट और कम नाप के पेट्रोल के बदले में रुपए 10 से 25000/- तक की कमाई होती है; तभी कर्मचारियों का वेतन का चेक मिलता है।

सभी खाद्य निरीक्षकों, सहा. जिला आपूर्ति अधिकारी से लेकर खाद्य नियंत्रक हरेन्द्र सिंग और हरेन्द्र सिंग से प्रभारी एसडीएम से लेकर मंत्री पारस जैन को भी पैसा हर जिले से पहुंचना है। बेशक जिलाधीश भी इन गैस एजेंसियों पेट्रोल पंपों गैस पंपों से मिले खाद्य नियंत्रक को प्रति पेट्रोल पंप रुपए 5000/- प्रति माह के हिस्से में से हिस्सेदार होता है। यही कारण है कि पेट्रोल, गैसे पंपों पर कम नापने और मिलावट के बाद भी पिछले 4 वर्षों से कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि कलेक्टर सुलेमान ने आदेश निकालकर हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल की लॉरी खाली होते समय खाद्य निरीक्षक, सहायक आपूर्ति अधिकारी अपनी लगाई सील तोड़कर पेट्रोल-डीजल की लॉरी खाली करवाता था, ताकि मिलावट की गुंजाइश न रहे, इंदौर के ही 40 से ज्यादा कुख्यात पेट्रोल पंप जिनके पास मिट्टी तेल की भी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो गांवों और शहरों के मान से अलग-अलग है, जनता का बांटने की अपेक्षा पेट्रोल, डीजल में मिलाकर बांटते हैं। स्वाभाविक है सारे शूअरों की शासकीय फौन जिसमें नाप-तौल के सारे निरीक्षक जो अपने-अपने क्षेत्र के पेट्रोल पंपों से रुपए 5 से 10 हजार की महीना वसूली करते हैं। कैसे गंदगी चाटकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे; यही हाल नापतौल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के बारे में गैस वालों का भी है। केंद्र सरकार कहती है 24 घंटे में सिलेंडर मिलना चाहिए, हर उपभोक्ता को दो सिलेंडर दिये जाने चाहिये। गैस पूरी तोलकर दी जानी चाहिये, के विपरीत पूरे प्रदेश में 7 से 15 दिन की बुकिंग के बाद मुश्किल से डिलेवरी, गैस सिलेंडर में पानी, कम गैस, अधिकांश उपभोक्ताओं के दो गैस सिलेंडरों के कनेक्शन का दूसरा सिलेंडर अवैध रूप से हर गैस एजेंसी पर मालिक की मिली भगत से हजारों को बांट रखे हैं। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चलाये जा रहे हैं। बाजार में ये हरामखोर गैस एजेंसी मालिक तत्काल में रुपए 550/- से रुपऐ 600/- में सिलेंडर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। आखिर ये धूर्त डकैत गैस एजेंसी मालिक, खाद्य नियंत्रक, एसडीएम और कलेक्टर बतायें कि ब्लेक में तत्काल रुपए 550/--600/- में केसे गैस घरेलू सिलेंडर कैसे उपलब्ध हो जाता है, जबकि बुकिंग करवाने पर उपभोक्ता को 7 से 15 दिन का इंतजार करनापड़ता है। इसी सबके चलते हर गैस एजेंसी का मालिक रुपए 20 से 50 हजार रुपए महीना इन शासकीय विभागों को बांटता है; और ये हरामखोरों की फौज महीना वसूली कर चुपचाप अजगरों की तरह अपने कार्यालयों की कुर्सी पर लिपटी पड़ी रहकर कागजी खानापूर्तियों में व्यस्त रहती है। यही हाल कंट्रोल दुकानों में एपीएल, बीपीएल के कार्ड धारकों को मिलने वाले गेहूं, चावल, शकर, मिट्टी के तेल के वितरण का गांवों से लेकर शहरों तक का है। इस संबंध में जब खाद्य नियंत्रक हरेन्द्र सिंग से इंदौर से बात की तो बोले मैं दिखवा रहा हूं। मैं आंकड़े निकलवा रहा हूं। इन हरामखोरों को मोटी वेतन, रुपए 50 लाख प्रतिमाह की वसूली, मिल जाती है तो ये क्यों देखेंगे जनता का दुःख,दर्द।

इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन के कार्यालय में फोन पर बात करने कोशिश की उज्जैन में तो जवाब मिला कि मंत्रीजी कार्यक्रम में गये हैं, उनके मोबाइल पर बात कीजिये उनका मोबाइल नं.-9425091497 लगाया तो मंत्रीजी ने नहीं उठाया, बेशक मंत्री को इन काले कारनामों से रिश्वत के रूप में न्यूनतम रुपए 10 करोड़ प्रतिमाह की आय होगी, वैसे भी मंत्री पारस जैनके भ्रष्टाचार के काफी कारनामे छप रहे हैं। यह भ्रष्ट मंत्री अपराधियों, भूमाफियाओं को न केवल संरक्षण देता है वरन 18 नवम्बर व 10 को तो इसने एक भूमाफिया किरण मोदी, पराग मोदी, पंकज मोदी, जिनके दादा स्व. मोहलाल मोदी ने सिंधिया रियासत में रहते हुए पूरी मोदी गली के मकानों 84 महादेव मंदिरों के मंदिर क्र. 15, 16, 17, 18 के मंदिरों और उससे जुड़ी भूमि पर पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से कब्जे कर रखे हैं। सामने रहने वाले श्री नरेन्द्रसिंग ठाकुर उर्फ पप्पू बाबा उसके बेटे हेमंत उर्फ चिंटू ठाकुर और श्रीमती पदमापति नरेन्द्र सिंग ठाकुर के विरुद्ध महाकाल थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाई। शाम 2-3 बजे जबकि इन तीनों भूमाफिया बंधुओं के किरण पंकज और पराग मोदी ने चिंटू उर्फ हेमंत ठाकुर उम्र 19 वष्र को पहले बुलाया और बाल पकड़कर मार-पीट करने लगे तब उनकी मां श्रीमती पदमा ठाकुर उसे बचाने पहुंची तो उसके साथ भी झूमा झटकी की गई, जिससे उनकी कलाई में काफी चोटें आई, मारपीट के अंदेशे में पप्पू ठाकुर पहले ही मकाहाल थाने में बैठे थे। इन तीनों भूमाफियाओं ने हेमंत उर्फ चिंटू ठाकुर और पदमा के साथ मारपीट भी की ऊपर से इस भ्रष्ट, धूर्त मंत्री ने इस भूमाफिया के लिये महाकाल थाने पर उल्टे ही श्री हेमंत ठाकुर और पदमा के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने का दबाव डालकर रिपोर्ट लिखवा दी, जबकि हेमंत उर्फ चिंटू ठाकुर और पदमा की महाकाल थाने के टुकड़ेखोर टीआई ने न तो रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी ओर न ही हेमंत और श्रीमती पदमा ठाकुर का मेडिकल कराया, मात्र इस जालसाल मंत्री पारस जैन के कहने पर।

इस घटना से भाजपा के इस भ्रष्ट मंत्री का चरित्र और कार्यप्रणाली स्पष्ट होती है कि कैसे गरीबों को परेशान करे अवैध जमीनों पर कब्जे करने वाले माफियाओं के इशारे पर ये हरामखोर मंत्री थाने में भी झूठी रिपोर्ट लिखवाने तक के लिये टीआई पर दबाव डालकर रिपोर्ट लिखवाने से भी नही बाज आते।

पूरे प्रदेश के 5000 से ज्यादा पेट्रोल, डीजल पंपों, गैस पंपों से औसतन रुपए 5 करोड़ प्रतिमाह, 2000 से ज्यादा गैस एजेंसियों से रुपए 2 करोड़ प्रति माह, 20000 से राशन दुकानों से रुपए 2 करोडत्र प्रतिमाह, केरोसिन की कालाबाजारी से रुपए 1 करोड़ के अतिरिक्त 2000 से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे और 3000 टन से ज्यादा गरीबी रेखा के ऊपर वालों का गेहूं, 1000 टन से ज्यादा चावल, 500 टन शकर की और इतना ही 500 टन से ज्यादा मध्यान्न भोजन के गेहूं के वितरण की अफरा-तफरी में रुपए 10 करोड़ से ज्यादा हर माह घोटाला किया जाता है। इसके साथ ही जैसा रुपया 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार म.प्र. में भी मूर्त रूप ले रहा है अंदर ही अंदर तो ये मानकर चलिये मंत्री पारस जैन भी रुपए 2-3 हजार करोड़ के मालिक होंगे, स्वाभाविक है भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त और वसूली में व्यस्त, को जनता की कहां परेशानी दिखेगी और कहां मिलावट और कम नाप दिखेगी। इंदौर में 19वष्र से पदस्थ सहा. आपूर्ति अधिकारी रमेश मीना जिसका फर्जी जाति प्रमाण पत्र है, जो कि रहने वाला गुना जिले की वीनागंज का था और जाति प्रमाण पत्र उसने सिरोंज तहसील जिला विदिशा से बनवाया था का विवादों के चले स्थानांतरण सिहोर कर दिया गया ताकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला दब जाए, जबकि श्री अजमेरा ने सभी अनु. जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के जाति पत्रों की फोटो कापी उसके रहे हुये ही मांगी थी, जिसे नौकरी से बाहर किया जाकर शासन के साथ 420 में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाना चाहिये था, मंत्री पारस जैन ने धन डकार कर स्थानांतरण कर उसे भी बचा लिया।

साप्ताहिक समय माया

आखिर क्यों, बर्बादी की कगार पर आ गया अमेरिका

अमेरिकी स्कूलों में स्वच्छंद यौनाचार

भारतीयों की श्रेष्ठता उसके सांस्कृतिक मूल्यों के कारण वर्तमान में अमेरिका में युवा पीढ़ी का ध्यान न तो पढ़ाई पर है और न ही उसकी भविष्य के प्रति जागरूकता, बार-बार अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर बुश और अब अमेरिका .....राष्ट्रपति अपने देश की युवा पीढ़ी को भारतीय और चीनी अप्रवासियों की युवा होती और स्कूल जाती पीढ़ी से सावधान रहने, उन्हें पढ़ाई में पीछे छोड़ने के लिस सार्वजनिक यंत्रों से अपनी जनता से आह्वान कर रहे हैं। तो कभी सरेआम चीनी और भारतीय युवा पीढ़ी के प्रति क्षेत्रीय अमेरिकी युवा पीढ़ी में उनको नौकरियों पर कब्जे और हथियाने के प्रति आक्रोशित कर रहे हैं।

आखिर विश्व का महान शक्तिशाली समझने और दुनिया को अपने तरीके से हांकने वाला ये देश चीनी और भारतीय युवा पीढ़ी से अपने ही देश में इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि इस राष्ट्र की युवा पीढ़ी में हिन्दू धार्मिक सयंम और चीनी युवा पीढ़ी में बौद्ध धर्म की एकाग्रता और यौनाचार की निश्चित आयु के आद ही भोगने की परंपराओं से वो कहीं न कहीं बंधे हुए हैं।

उसके विपरीत अमेरिकी स्कूलों में स्वच्छंद यौनाचार, स्कूलों में मुफ्त कंडोम का उपयोग उसकी युवा होती पीढ़ी को चड्डियों में उलझाकर अपनी शिक्षा से न केवल विमुख कर देता है वरन दिशाहीन बनाकर दिगभ्रमित भी कर देता है और कहानी दुनिया के सामने है। यह दिशाहीनता पूरे अमेरिका की युवा होती पीढ़ी और वर्तमान प्रौढ़ पीढ़ी के निकंमेपन के कारण पूर्णतः भारतीयों और चीनीयों पर निर्भर होकर रह गयी, यहां तक कि शासन चलाने के लिये भी उसे भारतीयों और चीनीयों पर जो कि उसके लिए घोर शत्रु होते हैं, काम चलाना पड़ रहा है। नासा से लेकर पेंटागन और वॉशिंगटन तक भारतीयों पर निर्भर रहते हैं।

भारत के केंद्रीय शासन के मानव संसाधन विभाग को इस तथ्य को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम अपनी स्कूली और महाविद्यालयीन शिक्षा में अपने ही भारतीय संयम की परंपराओं का पालन कर ही समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। यदि हमने भी अपने देश में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त शैतान संघ के इशारों पर चल कर अपने राष्ट्र की युवा होती पीढ़ी, युवा पीढ़ी को स्कूलों में कंडोम बांटकर स्वच्छंद यौनाचार की तरफ धकेला और संयमहीनता को बढ़ावा दिया तो हम भी अमेरिका की तरह स्वयं ही बर्बादी की कहानी लिखेंगे और राष्ट्र फिर गुलामी की तरफ बढ़ने लगेगा।

हमारे राष्ट्र की विशाल आबादी सच्चे अर्थों में हमारी आधारभूत समृद्धि का आधार है; बशर्ते कि वे पूर्ण शिक्षित और संयमित हों, संयम हमारी आर्थिक, सामाजिक उन्नति का ठोस आधार है। यौनाचार तत्काल में भले ही आकर्षण का केंद्र बन जाए परन्तु दीर्घकालीन अति यौनाचार सभी के लिए घातक और बर्बादी का कारण ही बनती है, जो अमेरिकी समाज में वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होरक, अमेरिकी सत्ताधीशों के लिये चहुं ओर परेशानी का कारण है। वर्तमान हालात ये हैं कि अमेरिका जो विश्व मं श्रेष्ठतम होने का दंभ भरता था, उसकी आंतरिक और बाहरी अर्थव्यवस्था भारतीयों पर निर्भर होने लगी है। इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उस राष्ट्र का राष्ट्रपति भारत आकर अपने उद्योगों के माल बेचने बेरोजगारी दूर करने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, अपनी साख बचाने, गुहार लगता है। यहां आकर झूठे वादे करता है; जैसा कि एक विक्रय प्रतिनिधि करता है और अपना माल बेचने की स्वीकृति और आदेश प्राप्त कर फुर्र हो जाता है।

यदि इसके मूल में जाकर अध्ययन करें कि आखिर अमेरिका को वर्तमान विपन्नता की स्थितियों के कारण क्या हैं, तो हम पाते हैं कि अत्यधिक संपन्नता से जो उसकी युवा होती पीढ़ी में जो स्वच्छंदता आयी, ऊपर से वहां की सरकारों ने उस पर नियंत्रण लगाने की अपेक्षा उल्टे उस स्वच्छंदता को बढ़ावा देकर, कंडोम संस्कृति और भत्तों का भुगतान किया। इसे पाक वह अपनी मूल आवश्यकता, पढ़ाई से विमुख होकर, चड्डी में उलझ अपने ही सहपाठियों पर गोलिया चलाने लगी, अपराधों में उलझ गयी। पढ़ाई खत्म होने पर बेरोजगारी भत्तों से जिंदगी चलने लगी और अर्थव्यवस्था बोझ बन गयी, अर्थात ज्यादा संपन्नता, उसका दुरुपयोग, स्वच्छंदता, संयमहीनता, स्वयं के लिये, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व का कभी भला नहीं कर पाती है। ये उदाहरण न केवल अमेरिका वरन ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के लिये ज्वलंत प्रमाण है। वक्त है, कि हम अपने यहां स्कूलों, कॉलेजों में अपनी युवा होती पीढ़ी, युवा पीढ़ी को जीवन के हर क्षेत्र में संयम और नियमों के व्यवहार सिखाकर भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापित कर न केवल विद्यार्थियों के स्वयं के जीवन में समाज में, राष्ट्र में वरन विश्व को पूर्ण संयम के साथ जीवन में चलकर चहुंदिशी समृद्धि का ठोस आधार स्थापित करें और विश्व में श्रेष्ठता सिद्ध करें।

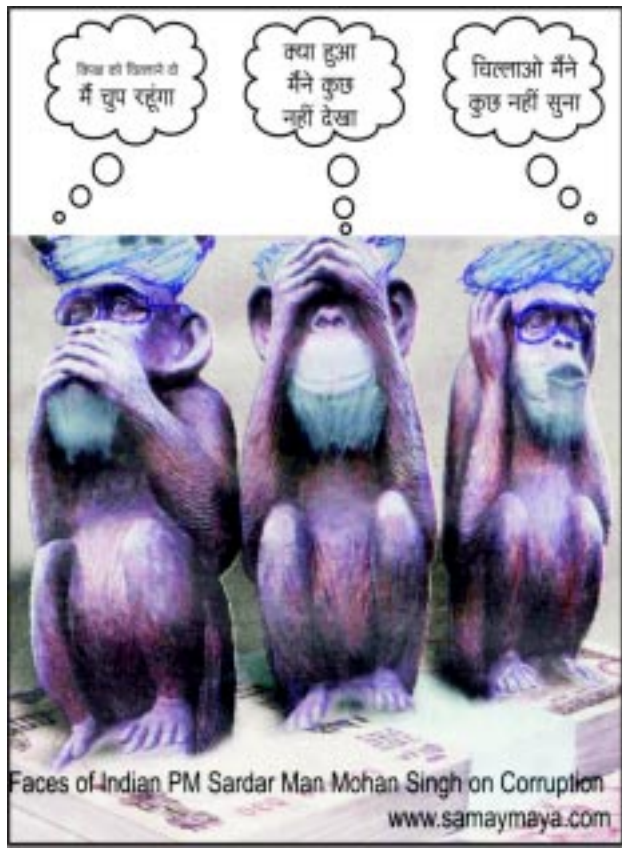

गांधी के अनुयायी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के असली चेहरे।

धन्य हैं, सुदर्शन आपने देश को सच बताया

पूरी कांग्रेस षड्यंत्रकारियों, जालसाजों का गिरोह

इंदिरा व राजीव की अंत्येष्टि में एक आंसू नहीं था, ... की में, मां बेटी झार-झार रोई थीं, कांग्रेसियों को इतिहास के आइने से बहुत डर लगता है

भोपाल में 10 नवंबर को संघ के प्रदर्शन के दौरान षड्यंत्रकारिणी सोनिया का जो सच बताया, तो स्वयं पदलोलुप दिग्गज पदाधिकारी स्वयं सेवकों को भी हजम नहीं हुआ, के. सुदर्शन ने जो सच बोला वो तो पूरा सच था ही, परन्तु सोनिया का पूरा इतिहास नहीं खोला गया।

समय माया अपने प्रकाशन के प्रारंभ से ही इस सच को न केवल लगातार प्रकाशित करता आ रहा है वरना हर कदम कांग्रेसी गिरोह में बैठे हर डकैत मंत्री के ....के साथ षड्यंत्रकारिणी सोनिया के राष्ट्र विरोधी कार्यों और उस पर उसके पिट्ठू मनमोहन की मोहर और पहल को भी लगातर प्रदर्शित और प्रकाशित कर रहा है। लगातार इसके विपरीत सत्ता की भूखी भाजप ाऔर उसकी जन्मदाता और संरक्षक जो राष्ट्रवादी होने का दंभ भरते हैं अब सत्ता की लोलुपता के चलते अपने ही वरिष्ठों का सच बोलने पर कैस अलग-थलग कर दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। उनका ये चरित्र, आदरणीय सुदर्शन जो कि एक राष्ट्रनिष्ठ भारतीय होने और राष्ट्र हित में षड्यंत्रकारिणी सोनिया के विरुद्धएक वाक्य बोलने पर जो किया उससे उजागर हो गया। ऐसा नहीं है कि श्री के.सुदर्शन ने यह जो कहा इसके पहले वर्षों से राष्ट्र प्रेमी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हुआ। 1965 में जिस तरह स्व. राजीव के जीवन में कैब्रिज में अमेरिका ने इस इटालियन माफिया की बेटी को जीवन में उतारकर स्व. इंदिरा गाधी को विवाह के लिए विवश कर उसका ईसाई पद्धति से राबर्ट बनाकर विवाह करवा दिया था, बाद में भारत में आने पर स्व. इंदिरा गांधी ने पुनः वैदिक रीति से विवाह करवाया, स्व. राजीव एयर इंडिया में पायलेट थे और अक्सर बाहर रहते थे। स्व. इंदिरा प्रधानमंत्री होने के नाते अत्यंत व्यस्त रहती थीं, इसका फायदा दूसरी ओर प्रधानमंत्री जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर बैठी सास, की पुत्रवधु होने का रुतबा, तीसरी ओर पूरे देश की सत्ता की गतिविधियों के चप्पे-चप्पे की बारीक से बारीक और अत्यंत

इंदिरा व राजीव की हत्या की षड्यंत्रकारी है, सोनिया

गोपनीय जानकारियां भी उसके चारों तरफ के वातावरण से मिल जाती थीं, जिसके बारे में वॉशिंगटन को पूरी जानकारी हो जाती थी, तो आखिर कैसे? 9 दिसंबर 1946 को स्टेफनो और पावला मैनो की .....गांव की विसेन्जा जिले इटली में जन्मी सोनिया एंटोनिया .....1964 में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के कैंब्रिज शहर के आवासी स्कूल ब्रिटेन में पढ़ने के लिए आई थी और अपनी जीविको पार्जन के लिए एक ग्रीफ रेस्टोरेंट में होटल वेट्रेस का काम करती थीं जहां 1965 जनवरी में राजीव से इसकी मुलाकात हुई, जहां से ये राजीव के साथ भारत आई और 1968 में यहां पर भी विवाह किया, बाकी कहानी पाठक स्वयं समझ सकते हैं। जो विकीपीडिया में सोनिया के बारे में है।

1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और स्व. इंदिरा गांधी की युद्ध से संबंधित हर रणनीति की खबर 15 से 20 मिनिट में अमेरिका को लग जाती थी, कैसे? उस समय युद्ध में हमारा सहयोगी था सोवियत रूस उसने अपना बेड़ा भारत की सहायता के लिये भेजा, तत्क्षल पाकिस्तान की सहायता के लिए अमेरिका ने भी 7वां बेड़ा भेज दिया था। स्व. इंदिरा गांधी ने लाहौर तक कब्जा करने की रणनीति पर जैसे ही अंजाम देने की तैयारी में आईं वैसे ही अमेरिका ने भारत को धमका दिया और कमजोर पड़ती पाकिस्तानी सेना से आत्मसमर्पण करवार कर नाटक और युद्ध का पटाक्षेप करवा कर लाहौर और पाकिस्तानी बर्बादी को रोकर बचा लिया।

अमेरिका की गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन

विकीलीक्स और समय माया के विरुद्ध षड्यंत्र

विश्व का इंटरनेट के महासागर में गूगल का क्या महत्व है यह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक दुनिया की 7 अरब की आबादी में से लगभग 4 अरब लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसकी व्याख्या की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस साइट के माध्यम से कम से कम भारत की 10 करोड़ आबादी के

सर्च पर दिखता है यह साइट कंप्यूटर हानि पहुंचा सकती है

इंटरनेट उपयोगकर्ता में से 3 करोड़ इसी के माध्यम से उपयोग करते हैं और चाही नई साइटों की तलाश करते हैं। इससे इसके उपयोग ओर चलन का महत्व स्पष्ट होता है। स्वाभाविक है जो शक्ति संपन्न होगा वह अपनी शक्ति का सदुउपयोग के साज्ञि दुरुपयोग भी करेगा ही नवम्बर 10 के मध्य से विकीलीक्स डाट आरग ने अमेरिकी कुकर्मों और विश्व के अन्य देशों के बारे में जानकारी के दस्तावेज अपनी साइटों पर लोड किये स्वाभाविक था कि उसमें भारत का भी बहुत सारा रिकार्ड था, जब तक देश में लोकसभा का सत्र चलता रहा तब तक भारत में विकीलीक्स की कोई भी साइटस को गूगल ने नहीं खुलने दिया, जब-जब गूगल पर विकीलीक्स के बारे में खोजबीन की गई इसने भारत में प्रिंट मीडिया में छपे जो दस्तावेजों की जानकारी दी जो भारत के अतिरिक्त दुनिया के अन्य देशें में खुल रही थी वहां से बड़े समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने जितना अपने समाचार पत्रों को भेजा उतना ही समचार पत्रों में प्रकाशित हुआ जबकि भारत अमेरिका की नजर में अभी भी गुलामों का न केवल पूरा देश है वरन वह भारत के विरुद्ध अनेकों षड्यंत्र पाकिस्तान के साथ मिलकर रचता ही रहता है। विकीलीक्स ने भारत के 1971 के भारत पाक युद्ध में की गई जालसाजियों के भी खुलासे किये ही होंगे।

भारत को अपना मित्र बताने वाले अमेरिका ने उस युद्ध में पाकिस्तान की सहायता के लिए 11 दिसम्बर 1971 को अपना 7वां बेड़ा भेजा था, उस युद्ध में रूस ने हमारा साथ दिया था। उस समय की तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हर फैसले की खबर अमेरिका को तत्काल कैसे मिल रही थी। इसका खुलासा भी वीकीलीक्स में होगां तत्काल के खुलासे में राहुल गांधी ने भारतीय हिन्दुओं के खिलाफ जो बोला था उसकी खबरें भी विदेशी मीडिया और विदेशों में बैठे भारतीयों ने ही संभवतः भारतीय मीडिया को उपलबध करवाई।

भारत में वीकिलीक्स की साइटों को रोकने के लिए कांग्रेसी गिरोह और भारत शासन ने मोटी रकम गूगल को भी दी और भारत संचार और विदेश संचार निगम के माध्यम से अपनी सत्ता का भरपूर उपयोग करते हुए भारत में साइटें ही नहीं खुलती हैं। इसी प्रकार का मिलता जुलता षड्यंत्र गूगल समय माया की साइटों के साथ भी चलाया जा रहा है, पिछले छह माह से ज्यादा समय से गूगल क्रोम, मोजिला इंटरनेट ब्राउजर से समय माया की साइट तो खुलती ही नहीं है। साथ ही खोज करने पर समय माया राष्ट्रीय समाचार पत्र लिखकर नीचे स्पष्ट लिखा रहता हैख यह आपका कंप्यूटर खराब कर सकती है। सैंकड़ों लोगों ने यह शिकायत हमें भी की है, जबकि हम प्रायः इंटरनेट एक्सप्रोरर खोलकर हर रोज ही साइट अपडेट करते हैं।

बेशक यह सब कांग्रेस गिरोह की सरकारी पैसा खर्च करके हमारी साइट की सच्चाईयां जनता तक न पहुंचने के लिए ही किया जा रहा है और विकिलीक्स की साइट के भारत में सेंसर करने के षड्यंत्र करने से स्पष्ट होती हैं।

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु/ 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इंदौर से मुद्रित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालयः 0731- 2530859, मो. 9300755803